एक्ज़िम बैंक EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस:
निर्यात लाभ

जून 2014
खंड XXVIII • अंक II

इस अंक में

5 ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ भारत के व्यापार का आकलन
6 एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं
7 भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए उज्ज्वल भविष्य
8 गत तिमाही
9 वैश्विक क्षेत्र में भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को अभूतपूर्व वृद्धि
10 एक्ज़िम बैंक समाचार
11 अफ्रीका में खाद्य एवं कृषि में एफ डी आई
12 एक्ज़िम बैंक कार्यकलाप तथा साहित्य समीक्षा
13 देशों का सूक्ष्मावलोकन
14 मुद्रा की प्रवृत्तियां
15 एक्ज़िम बैंक के कार्य-निष्पादन की विशेषताएं - 2013-14
16 भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य
17 भारतीय व्यापार का प्रदर्शन

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

पूर्व अफ्रीकी समुदाय के साथ भारत के बढ़ते व्यापार संबंध

पूर्व अफ्रीकी समुदाय (ईएसी) की स्थापना हेतु संधि के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत स्थापित एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है. इसका मुख्यालय अरूशा, तंजानिया में है. समुदाय के सदस्यों में बुरूंदी, केन्या, रवांडा, यूगांडा तथा तंजानिया शामिल हैं. ईएसी अफ्रीकी क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा है जिसका अफ्रीकी क्षेत्र के कुल भू-क्षेत्रफल में 5.8 प्रतिशत, कुल जनसंख्या में 13.5 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 5.3 प्रतिशत हिस्सा है.

ईएसी देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंध

पूर्वी अफ्रीकी देशों के भारत के साथ ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ आर्थिक संबंध रहे हैं और इनमें से अधिकांश टेक्सटाइल, कृषि-व्यवसाय जैसे क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों में निवेशगत व्यापार के माध्यम से रहा है. हिंद महासागर से पूर्वी अफ्रीका की निकटता भारत के साथ व्यापार तथा निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए सोने पर सुहागा है.

ईएसी क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार संबंधों की प्रगाढ़ता को इस तथ्य से आंका जा सकता है कि भारत तथा ईएसी के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2002 के 490.8 मिलियन यूएस डॉलर से 13 गुना बढ़कर 2012 में 6.6 बिलियन यूएस डॉलर हो गया (चार्ट). यह वृद्धि ईएसी सदस्यों के भारत के साथ निर्यात और आयात दोनों खंडों में रेखांकित हुई है तथापि निर्यात खंड में वृद्धि अधिक रही है. क्षेत्र को बढ़े हुए निर्यात की बदौलत भारत का इस क्षेत्र के साथ व्यापार संतुलन धनात्मक रहा है और व्यापार अधिशेष 2002 के 247.8 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2012 में 5.3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है.

भारत के व्यापारिक भागीदार के रूप में इसका बढ़ता महत्व इस बात से रेखांकित होता है कि ईएसी देशों को भारत का निर्यात 2002 के 369.3 मिलियन यूएस डॉलर से 16 गुना बढ़कर 2012 में 5.9 बिलियन यूएस डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है. परिणामस्वरूप, अफ्रीका को भारत के कुल निर्यात में ईएसी देशों का हिस्सा 2002 में 12.2 प्रतिशत से बढ़कर 2012 में 21.7 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है. ईएसी क्षेत्र से भारत का आयात 2002 के 121.5 मिलियन यूएस डॉलर से 5 गुना बढ़कर 2012 में 624.1 मिलियन यूएस डॉलर हो गया है जो अफ्रीका से भारत के कुल आयात का 1.5 प्रतिशत है.

केन्या ईएसी देशों में भारत का अग्रणी निर्यात गंतव्य स्थान है और दक्षिण अफ्रीका के बाद अफ्रीकी देशों में दूसरा सबसे बड़ा है. ईएसी को भारत के कुल निर्यात में केन्या का 63.6 प्रतिशत हिस्सा है. इसी वर्ष के दौरान ईएसी क्षेत्र को अन्य प्रमुख निर्यात गंतव्य स्थानों में तंजानिया (ईएसी को निर्यात का 27 प्रतिशत) और यूगांडा (7.6 प्रतिशत) शामिल हैं.

जहां तक आयात का संबंध है, तंजानिया ईएसी देशों में भारत को सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है जो मुख्यतः देश से बड़ी मात्रा में काजू के आयात के कारण है. ईएसी क्षेत्र से भारत के कुल आयात में तंजानिया का हिस्सा 78.9 प्रतिशत रहा. इसके बाद केन्या (क्षेत्र से भारत के कुल आयात का 16.6 प्रतिशत) और यूगांडा (4.5 प्रतिशत) का स्थान रहा.

ईएसी क्षेत्र को भारत के निर्यात समूह में खनिज ईंधन सबसे बड़ी मद है जिसका 2012 में क्षेत्र को भारत के कुल निर्यात में 52.7 प्रतिशत हिस्सा रहा. ईएसी क्षेत्र को भारत के निर्यात की अन्य

चार्ट : ईएसी के साथ भारत का व्यापार

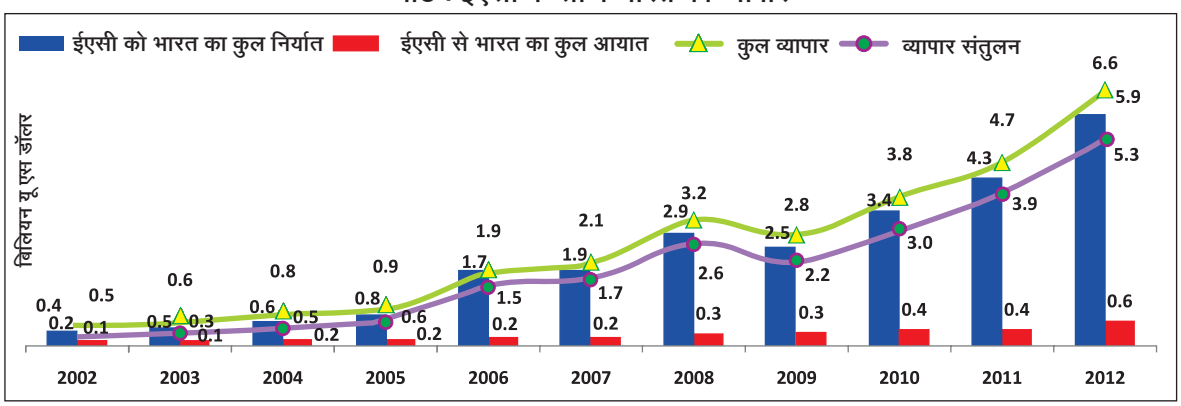

स्रोत : आईटीसी जिनेवा और एक्ज़िम बैंक विश्लेषण

महत्वपूर्ण मदों में फार्मास्युटिकल उत्पाद, मशीनें एवं उपकरण, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन, लौह एवं इस्पात तथा चीनी एवं चीनी कन्फेक्शनरी शामिल हैं.

काजू तथा खाद्य फल एवं गिरियां ईएसी से भारत के आयात समूह में सबसे बड़ी मदें हैं जिनका 2012 में क्षेत्र से भारत के कुल आयात में 25.7 प्रतिशत हिस्सा रहा. ईएसी क्षेत्र से अन्य महत्वपूर्ण आयात मदों में मोती एवं बहुमूल्य रत्न, खाद्य सब्जियां एवं कंद, कपास, कॉफी, चाय एवं मसाले, अकार्बनिक रसायन, लौह एवं इस्पात, अपरिष्कृत तथा परिष्कृत चमड़ा शामिल हैं.

ईएसी देशों के साथ भारत के निवेश की प्रवृत्तियां

ईएसी देशों ने अपने वृद्धि स्तरों को बनाए रखने और प्रौद्योगिकी अंतरण में एफडीआई की महत्ता को स्वीकार किया है. द्विपक्षीय निवेश संवर्धन तथा संरक्षण करार (बीआईपीए) पर केन्या तथा तंजानिया के साथ भारत की बातचीत चल रही है. इस करार का उद्देश्य इनमें से किसी भी देश में स्थित कंपनियों द्वारा एक-दूसरे के क्षेत्र में निवेश के लिए पारस्परिक प्रोत्साहन, संवर्धन एवं संरक्षण देना है. भारत ने केन्या, यूगांडा तथा तंजानिया के साथ आय पर कर के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए एक व्यापक दोहरा कराधान परिहार करार (डीटीएए) पर हस्ताक्षर भी किए हैं. जहां तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संचयी अंतर्वाह का संबंध है, अप्रैल 2000 से मार्च 2014 के दौरान 21.1 मिलियन यूएस डॉलर का सर्वाधिक निवेश केन्या से आया जो इस अवधि के दौरान ईएसी क्षेत्र से भारत में कुल निवेश प्रवाह का 88.6 प्रतिशत रहा. तंजानिया 1.6 मिलियन यूएस डॉलर के निवेश के साथ ईएसी देशों में भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत है और उसके बाद 1.1 मिलियन यूएस डॉलर के निवेश के साथ यूगांडा का स्थान रहा.

संचयी रूप से, अप्रैल 1996 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान ईक्विटी, ऋण तथा जारी गारंटियों की दृष्टि से संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में ईएसी क्षेत्र में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश 276 मिलियन यूएस डॉलर रहा. केन्या ने इस अवधि के दौरान भारत से 163.8 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य का निवेश (क्षेत्र को भारत के कुल निवेश का 59.4 प्रतिशत) आकृष्ट किया. केन्या के बाद तंजानिया इस अवधि के दौरान दूसरा सर्वाधिक अनुकूल गंतव्य स्थान रहा जिसका क्षेत्र को कुल एफडीआई बहिर्वाह में 22.3 प्रतिशत हिस्सा रहा.

ईएसी देशों को भारत की निर्यात संभाव्यता

ईएसी देशों को भारत की निर्यात संभाव्यता का निर्धारण ईएसी देशों के आयात समूह के विश्लेषण, लक्ष्य देशों की अनुरूपी आयात मांग के साथ भारत की निर्यात क्षमता और ईएसी देशों के प्रमुख मदों के आयात समूह में भारत के कम हिस्से के विश्लेषण के आधार पर किया गया है. तदनुसार, प्रमुख मदें , जिनमें भारत ईएसी देशों को निर्यात करने की संभाव्यता रखता है, उनमें शामिल हैं रेलवे से इतर भिन्न वाहन (एचएस-87), मशीनरी एवं उपकरण (एचएस-84), इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (एचएस-85), अनाज (एचएस-10), लौह एवं इस्पात (एचएस-72), प्लास्टिक एवं प्लास्टिक की वस्तुएं (एचएस-39), खनिज ईंधन, तेल एवं आसवन उत्पाद (एचएस-27), चीनी एवं चीनी कन्फेक्शनरी (एचएस-17), पेपर एवं पेपरबोर्ड (एचएस-48), पशु, वनस्पति वसा तथा तेल (एचएस-15), अन्य निर्मित वस्त्र वस्तुएं एवं सेट (एचएस-63), फर्नीचर, लाइटिंग, साइनेज तथा प्रीफैब्रीकेटेड बिल्डिंग (एचएस-94), ऑप्टिकल, फोटो, तकनीकी एवं चिकित्सा उपकरण (एचएस 90), जूते, गेटर तथा पुरजे (एचएस -64), कपास (एचएस-52) तथा परिधान, सहायक सामग्री, बुनाई या कसीदाकारी की गई वस्तुएं (एचएस-61).

ईएसी क्षेत्र में भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक)

एक्ज़िम बैंक की स्थापना निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माल एवं सेवाओं के निर्यात तथा आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा 1982 में की गई थी.

वित्तपोषण कार्यक्रम

ऋण –व्यवस्था

ईएसी क्षेत्र में एक्ज़िम बैंक के पास यूगांडा को छोड़कर सभी देशों को शामिल करते हुए यथा 31 मार्च, 2014 को 600.7 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य की भारत सरकार द्वारा समर्थित 10 ऋण -व्यवस्थाएं हैं. इसके अलावा, एक्ज़िम बैंक ने पूर्व एवं दक्षिण अफ्रीकी व्यापार एवं विकास बैंक (पीटीए बैंक) तथा अफ्री-एक्ज़िम बैंक को 95 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य की 5 ऋण-व्यवस्थाएं सीधे प्रदान की हैं.

परियोजना निर्यात के लिए सहायता

एक्ज़िम बैंक समुद्रपारीय औद्योगिक टर्न-की परियोजनाओं, सिविल निर्माण संविदाओं, आपूर्तियों तथा तकनीकी एवं परामर्शी सेवा संविदाओं के लिए भारतीय परियोजना निर्यातकों को निधिक एवं गैर-निधिक दोनों सुविधाएं प्रदान करता है. 31 मार्च 2014 को ईएसी क्षेत्र में भारतीय परियोजना निर्यातकों द्वारा प्राप्त चालू 18 परियोजना निर्यात संविदाओं का मूल्य 30.1 बिलियन यूएस डॉलर रहा. ये संविदाएं विद्युत (उत्पादन एवं पारेषण) तथा परामर्शी जैसे क्षेत्रों में हैं.

विदेशों में संयुक्त उद्यमों हेतु वित्त

एक्ज़िम बैंक भारतीय कंपनियों को संयुक्त उद्यमों तथा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों के माध्यम से अपने परिचालनों के वैश्वीकरण करने के उनके प्रयासों में सहायता करता है. ईएसी क्षेत्र में एक्ज़िम बैंक ने फार्मास्युटिकल, विनिर्माण तथा प्लास्टिक एवं पैकेजिंग जैसे सेक्टरों में केन्या, तंजानिया तथा यूगांडा में 354.4 मिलियन रुपये मूल्य की राशि से ऐसे छः उद्यमों को सहायता प्रदान की है.

बी सी-एनईआईए के अंतर्गत क्रेता ऋण

भारत से परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने पर एक्ज़िम बैंक का जोर भारत सरकार के राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के अंतर्गत क्रेता ऋण कार्यक्रम के शुरू हो जाने से और बढ़ गया है. ईएसी देशों सहित विभिन्न अफ्रीकी देशों को भारत से कई परियोजना निर्यातों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता पर विचार किया जा रहा है.

संस्थागत संबद्धताएं तथा व्यवस्थाएं

एक्ज़िम बैंक ने अफ्री-एक्ज़िम बैंक में भी ईक्विटी ली है और अफ्रीकी विकास बैंक, पूर्व एवं दक्षिण अफ्रीकी व्यापार एवं विकास बैंक (पीटीए बैंक) तथा अफ्रीकी एक्ज़िम बैंक के साथ कई सहयोग ज्ञापनों (एमओसी) और सहमति ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.

ईएसी देशों के साथ द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंध बढ़ाने के लिए रणनीतियां एवं अनुशंसाएँ

अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते इस क्षेत्र में वृद्धि को गति नहीं मिल रही है. अतः ई ए सी देशों के लिए यह जरूरी है कि वे परस्पर और शेष विश्व के साथ अच्छी कनेक्टिविटी के लिए अपने राजमार्गों, रेलमार्गों और पोर्टों को विकसित करें. भारतीय निवेशक राजमार्गों तथा रेलमार्गों के विकास, रेलवे नेटवर्क तथा पोर्ट के विकास में उनकी मदद कर सकते हैं. इससे क्षेत्रीय एकीकरण में भी काफी सहायता मिलेगी.

क्षेत्र में बिजली का संकट भी है जिसका कारण अपर्याप्त, अविश्वसनीय तथा महंगा विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर है. तेल एवं गैस की नई खोज से क्षेत्रीय आधार पर विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का सुनहरा अवसर है. भारत राष्ट्रीय ऊर्जा ग्रिडों को जोड़कर क्षेत्रीय ऊर्जा बाजार को बढ़ावा देने में ईएसी देशों की सहायता कर सकता है.

क्षेत्र के अधिकांश देशों में कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप मजबूत हैं और इनका निर्यात इन देशों के लिए महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जन में मदद करता है. भारतीय कंपनियां कौशल विकास, क्षमता सृजन, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, बीज व गुणवत्तापूर्ण निविष्टियों की आपूर्ति, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और जैव-प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु इन देशों में निवेश कर सकती हैं.

ईएसी की विकास रणनीति के अनुरूप, विशेषकर क्षमता निर्माण क्षेत्र में भविष्य में काफी संभावनाएँ हैं जिसमें भारत की भागीदारी महत्वपूर्ण हो सकती है. पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों, वनरोपण में सहायता और द्विपक्षीय व्यवस्थाओं जैसे वापसी खरीद (बाय बैक) व्यवस्था के माध्यम से प्राकृतिक तथा खनिज संसाधनों के विकास तथा खोज में भारत इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन संपन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाना भारत-ईएसी वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है.

भारतीय कंपनियां ईएसी देशों में भारतीय शैली के विश्वस्तरीय होटल तथा रिसॉर्ट विकसित करने पर फोकस कर सकती हैं. इसके अलावा, ईएसी देशों की समृद्ध सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताओं और पेड़-पौधे एवं जीव-जंतुओं में विशाल जैविक विविधता को देखते हुए भारतीय उद्यमी विभिन्न प्रकार के पर्यटन उत्पादों जैसे जोखिम पर्यटन, तटीय तथा सफारी पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, वाइल्डलाइफ पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन तथा सांस्कृतिक पर्यटन को विकसित करने पर विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं.

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में भारत महत्वपूर्ण देश है; भारतीय आईटी फर्में ईएसी क्षेत्र में अवसरों की तलाश कर सकती हैं और ई-गवर्नेंस, वित्तीय सेवाएं तथा ई-शिक्षा के क्षेत्रों में सहायक या संयुक्त उद्यमों में निवेश कर सकती हैं. भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा सेवाएं प्रदान करने में अपनी विशेषज्ञता को भी बांट सकती हैं.

भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं भी इस क्षेत्र में अधिक शाखाएं तथा प्रतिनिधि कार्यालय खोलने और क्षेत्र में चुनिंदा बैंकों के साथ करस्पोंडेंट बैंकिंग संबंधों को विकसित करने की संभावनाओं की तलाश कर सकती हैं। इससे वाणिज्यिक संबंधों को सुगम बनाने और विकसित करने में मदद मिलेगी. ईएसी में निवेश संवर्धन एजेंसियों तथा वाणिज्य मंडलों के साथ घनिष्ठ सहयोग तथा सहबद्धताओं का निर्माण क्षेत्र में निवेश अवसरों के बारे में सूचना तक पहुंच बढ़ाने में सहायक होगा.

विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय निधीयन एजेंसियां क्षेत्र में कुछ प्रमुख विकास परियोजनाओं को समर्थन देती हैं तथा उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं. इन निधिक परियोजनाओं पर विशेष ध्यान तथा भारतीय परियोजना एवं सेवा निर्यातकों द्वारा बढ़ती सहभागिता इस क्षेत्र में भारत की सशक्त मौजूदगी को बढ़ावा देने का कार्य करेगी.

आईटीसी के साथ एक्ज़िम बैंक का सहमति ज्ञापन (एमओयू)

एक्ज़िम बैंक ने उद्यम तथा क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सहायता करने और बाजार विश्लेषण एवं अनुसंधान सहित व्यापार आसूचना में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2014 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (आईटीसी) के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. एक्ज़िम बैंक तथा आईटीसी 2014 से 2020 के दौरान अफ्रीका के लिए भारत की व्यापार तरजीही सहायता परियोजना (सीटा) को सहयोग प्रदान करेंगे. यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) द्वारा निधिक, सीटा परियोजना व्यापार तथा निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आईटीसी की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है. छह वर्षीय इस परियोजना का उद्देश्य पांच पूर्व अफ्रीकी देशों ईथियोपिया, केन्या, रवांडा, तंजानिया तथा युगांडा से भारत को निर्यात बढ़ाने में मदद करना है. यह परियोजना अफ्रीका में निजी क्षेत्र को भारत से जोड़ने में सहायक होगी जिससे साउथ-साउथ सहयोग को बल मिलेगा. इस परियोजना से पूर्व अफ्रीकी लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई), अफ्रीका से आयात करने वाली तथा उसमें निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां तथा राष्ट्रीय व्यापार सहायता संस्थान (टी एस आई) लाभान्वित होगें.

परियोजना का उद्देश्य व्यापार किए जा रहे उत्पादों की रेंज में विविधता लाना और रोजगार एवं आय के अवसर सृजित करने में सहायता करना है. पूर्वी अफ्रीका तथा भारतीय कंपनियों के बीच बेहतर संबंधों के माध्यम से सीटा व्यवसाय को बढ़ावा देने में सहायता करेगा. इसका उद्देश्य अफ्रीका तथा भारत के बीच माल एवं सेवाओं के अधिक प्रवाह के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए पूर्व अफ्रीकी कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना भी है.

4 कारोबारी अवसर तथा प्राप्त संविदाएं

I कारोबारी अवसर

यथा जून 2014 को नई परियोजनाएं

देश / निष्पादक एजेंसी	परियोजना / संक्षिप्त कार्यक्षेत्र	निधीयन एजेंसी
निदेशक (भंडार एवं आपूर्ति) का कार्यालय तथा लाइन निदेशक प्रापण, लॉजिस्टिक्स तथा आपूर्ति प्रबंधन केन्द्रीय चिकित्सा भंडार डिपो (सी.एम.एस.डी.) तेजगांव, ढाका -1208 बांग्लादेश **संपर्क:** टेली- +9129231 फोन- +9126547 ईमेल - cmsdstore@dhaka.net	**स्वास्थ्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम** परियोजना में स्वास्थ्य, जनसंख्या एवं पोषण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचपीएनएसडीपी) के लिए कैथ लैब उपकरणों का प्रोक्योरमेंट शामिल है.	**विश्व बैंक** 50 मि. यूएस डॉलर
मंत्री-स्तरीय निविदा समिति परिवहन एवं संचार मंत्रालय सचिवालय कार्यालय, तल मंजिल, एमटीसी भवन, वेस्ट गेट माल, गैबोरोन, बोत्सवाना, **संपर्क :** सुश्री एम थॉमस मंत्रीस्तरीय निविदा समिति टेली: + 2673612000	**एकीकृत परिवहन परियोजना (बीआईटीपी)** परिवहन एवं संचार मंत्रालय के लिए सूचना संचार तथा प्रौद्योगिकी रणनीति के विकास के लिए परामर्शी सेवाएं.	**विश्व बैंक** 30 मि. यूएस डॉलर
भूटान पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड यार्डेन लैम, पो बॉक्स नं. 580, थिम्पु भूटान **संपर्क:** महाप्रबंधक पारेषण निर्माण विभाग (टीसीडी) टेली: + 975-2-325095 (विस्तार 200) फैक्स: 975-2-331218 ई-मेल : shamsherpradhan@bpc.bt	**ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा विकास परियोजना** कार्य में सामद्रुप जोंखार में मोटांगा से फुंटशोथांग तक 132 केवी डबल सर्किट टॉवर टाइप वितरण लाइन की आपूर्ति तथा निर्माण शामिल है.	**एशियाई विकास बैंक** 185 मि. यूएस डॉलर
जिम्बाब्वे मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड क्राउन एजेंट्स, सेंट निकोलस हाउस, सेंट निकोलस रोड, सुरे एस एम1 1ईएल यूनाईटेड किंगडम **संपर्क:** श्री केरेन हैरीज, परियोजना प्रबंधक टेली : + 44 20 8643 3311 फैक्स: + 44 20 8643 4502 ई-मेल : zimfundpa@crownagents.co.uk	**आपातकालीन बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पुनर्वास परियोजना चरण II** इस परियोजना का मूल उद्देश्य देश में ह्वांग पॉवर स्टेशन की पारेषण, उप-पारेषण तथा वितरण सुविधाओं के पुनर्वास के माध्यम से पर्यावरण अनूकूल ढंग से बिजली की पर्याप्त तथा विश्वसनीय आपूर्ति में सहायता करना है.	**अफ्रीकी विकास बैंक** 300 मि, यूएस डॉलर

II प्राप्त संविदाएं

भारतीय कंपनियों / परामर्शदाताओं द्वारा प्राप्त चुनिंदा संविदाएं

अपर इंडस्ट्रीज लि. मुंबई	ईथियोपिया की विद्युत आपूर्ति (ग्रामीण) विस्तार परियोजना के लिए एएएसी 95एमएम2 की आपूर्ति हेतु संविदा **विश्व बैंक समूह द्वारा निधिक**
साई कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्रा. लि., अहमदाबाद	अंगोला की जल क्षेत्र संस्थागत विकास परियोजना के लिए क्वितो तथा हुआम्बो जल आपूर्ति प्रणालियों के पुनर्वास हेतु डिजाइन, जांच एवं कार्य पर्यवेक्षण, **विश्व बैंक समूह द्वारा निधिक**
केईसी इंटरनेशनल लि., मुंबई	युगांडा की विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना के लिए कवांदा मसाका 220केवी ट्रान्समिशन लाइन के लिए संयंत्र एवं उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना तथा सम्बद्ध स्टेशनों का उन्नयन / निर्माण (लॉट 1) **विश्व बैंक समूह द्वारा निधिक**
वैपकॉस लिमिटेड, नई दिल्ली	अंगोला की जल क्षेत्र संस्थागत विकास परियोजना के अंतर्गत युइज (अंगोला) के पेरी शहरी क्षेत्रों में नेटवर्क तथा हाउस कनेक्शनों के लिए डिजाइन, जांच एवं कार्य का पर्यवेक्षण , **विश्व बैंक समूह द्वारा निधिक**

ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ भारत के व्यापार का आकलन

ब्रिक्स पांच अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह अर्थात् ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका के लिए एक संक्षिप्त शब्द है. प्रारंभ में इसे ब्रिक कहा जाता था, उस समय दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था. इस समूह को यह नाम 'बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स' शीर्षक से प्रकाशित एक आलेख में जिम ओ नील द्वारा 2001 में प्रदान किया गया था. इस आलेख का निष्कर्ष यह था कि अगले10 वर्षों में विश्व जीडीपी में ब्रिक और विशेषकर चीन का प्रभाव बढ़ेगा जिससे ब्रिक में राजकोषीय तथा मौद्रिक नीति के वैश्विक आर्थिक प्रभाव के बारे में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठे. 2003 में उनकी रिपोर्ट 'ड्रीमिंग विद ब्रिक्स: द पाथ टु 2050' में उल्लिखित है कि 2050 तक ये अर्थव्यवस्थाएं एक साथ मिलकर जी-6 देशों , जर्मनी, जापान,यूएस, फ्रांस तथा इटली की अर्थव्यवस्थाओं से बड़ी होंगी. 13 अप्रैल, 2013 को दक्षिण अफ्रीका को इस सूची में शामिल किया गया जिससे 'ब्रिक्स' (ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका) की उत्पत्ति हुई.

ब्रिक्स सदस्यों के साथ भारत का व्यापार

हाल के वर्षों में ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में काफी महत्वपूर्ण हो गयी हैं. ब्रिक्स सदस्यों के साथ भारत का व्यापार 2004 के 15.9 बिलियन यूएस डॉलर से छह गुना बढ़ते हुए 2013 में 97.3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया. तथापि, व्यापार में इस वृद्धि का आधार बढ़ता व्यापार घाटा है जो भारत ब्रिक्स सदस्यों के साथ बनाए रखता है और जो 2004 के 3.6 बिलियन यूएस डॉलर से दस गुना बढ़कर 2013 में 35.9 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है (चार्ट). ब्रिक्स सदस्यों को भारत का निर्यात 2004 में 6.2 बिलियन यूएस डॉलर से 19.5 प्रतिशत की सीएजीआर की दर से बढ़कर 2013 में 30.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है. जबकि आयात 2004 के 9.7 बिलियन यूएस डॉलर से 23.8 प्रतिशत की सीएजीआर की दर से बढ़कर 2013 में 66.6 बिलियन यूएस डॉलर हो गया.

ब्रिक्स सदस्यों में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है. 2013 में ब्रिक्स सदस्यों को भारत के कुल निर्यात में इसका 53.4 प्रतिशत और इसी अवधि के दौरान ब्रिक्स सदस्यों से भारत के कुल आयात में 55.5 प्रतिशत हिस्सा रहा.

ब्रिक्स को भारत की प्रमुख निर्यात मदों में खनिज ईंधन, तेल तथा इसके आसवन उत्पाद (2013 में निर्यात का 18.8 प्रतिशत), कपास (16.1 प्रतिशत), तांबा तथा उसकी वस्तुएं (6.4 प्रतिशत), अयस्क, धातु-मल तथा राख (5.7 प्रतिशत) और आर्गेनिक रसायन (5.3 प्रतिशत) शामिल हैं.

ब्रिक्स से भारत की प्रमुख आयात मदों में इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (2013 में कुल आयात का 21.8 प्रतिशत), कपास (16.1 प्रतिशत), मशीनरी एवं उपकरण (15 प्रतिशत), मोती, बहुमूल्य पत्थर तथा धातु (8.5 प्रतिशत), ऑर्गेनिक रसायन (8.2 प्रतिशत) तथा खनिज ईंधन, तेल तथा इसके आसवन उत्पाद (7 प्रतिशत) शामिल हैं.

ब्रिक्स को भारत का निर्यात ब्रिक्स सदस्यों से भारत के आयात के आधे से भी कम है. ब्रिक्स सदस्यों में भारत का चीन के साथ सर्वाधिक व्यापार घाटा (2013 में 35.2 बिलियन यूएस डॉलर) रहा, उसके बाद दक्षिण कोरिया (1.6 बिलियन यूएस डॉलर) और रूस (1.4 बिलियन यूएस डॉलर) का स्थान रहा. ब्राजील एकमात्र देश है जिसके साथ भारत का 2013 में 2.3 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार अधिशेष था.

अतः भारत चीन, दक्षिण अफ्रीका तथा रूस को अपना निर्यात बढ़ाने पर विचार कर सकता है. ब्रिक्स के साथ भारत के व्यापार घाटे में चीन का हिस्सा 98 प्रतिशत है. चुनिंदा वस्तुएं जिनमें भारत चीन को अपना निर्यात बढ़ाने पर विचार कर सकता है, उनमें शामिल हैं : इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (एचएस- 85), खनिज ईंधन तथा इसके आसवन उत्पाद (एचएस-27), मशीनरी (एचएस-84), प्लास्टिक तथा उसकी वस्तुएं (एचएस-39), रेलवे से इतर वाहन (एचएस-87), ऑर्गेनिक रसायन (एचएस-29), लौह एवं इस्पात (एसएच-72), रबड़ एवं उसकी वस्तुएं (एचएस-40), विविध रसायन उत्पाद (एचएस-38), औषधि उत्पाद (एचएस-30), लौह एवं इस्पात की वस्तुएं (एचएस-73), मछली एवं क्रस्टेशिया (एचएस-03), मानव निर्मित फिलामेंट (एचएस-54), मानव निर्मित स्टेपल फाइबर (एचएस-55), परिधान वस्तुएं एवं सहायक सामग्री, गैर बुनी या गैर क्रोशेट (एचएस-62), चमड़े की वस्तुएं तथा यात्रा सामान (एचएस-42), जूते, गेटर तथा उसके पुरजे (एचएस-64), परिधान वस्तुएं एवं सहायक सामग्री, बुने या क्रोशेट (एचएस-61).

भारत विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में चीनी निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है. भारत में औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन (एमओयू) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है.

चार्ट : ब्रिक्स सदस्यों के साथ भारत का व्यापार

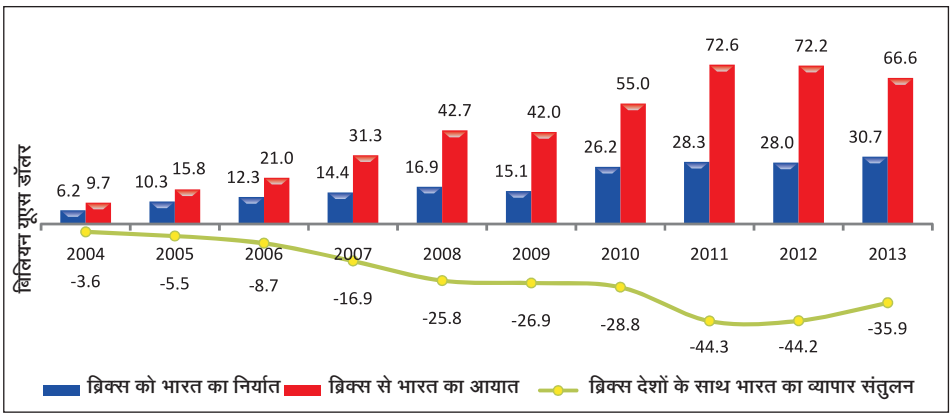

स्रोत : ट्रेडमैप, यूएनकामट्रेड से प्राप्त

ब्रिक्स समिट

छठी ब्रिक्स समिट 14-16 जुलाई,2014 के दौरान फोर्तलिजा, ब्राजील में आयोजित की गई. पांचों सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों तथा सरकार प्रमुखों ने इस समिट में भाग लिया. समिट का थीम थी 'समावेशी बैंकिंग : टिकाऊ समाधान'. ब्रिक्स नेताओं ने फोर्तलिजा घोषणा तथा कार्य योजना को अंगीकार किया. समिट के दौरान हस्ताक्षर किए गए अन्य दस्तावेजों में ब्रिक्स देशों की निर्यात ऋण एजेंसियों के बीच सहमति तथा सहयोग ज्ञापन, नवोन्मेष सहयोग करार, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था सृजित करने पर करार तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना संबंधी करार आदि हैं.

6 एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं

भारतीय एक्ज़िम बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लघु एवं मझौले उद्यमों पर विशेष बल के साथ प्रभावी बाजार प्रवेश व्यवस्था के रूप में ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करने पर विशेष जोर दिया है. एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, सरकारी और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है. ये ऋण-व्यवस्थाएं उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित भुगतान शर्तों पर विकासपरक तथा बुनियादी संरचना, परियोजना, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं. इनके अंतर्गत भारतीय निर्यातक शिपिंग दस्तावेज के एवज में पर एक्ज़िम बैंक से पात्र मूल्य का भुगतान दायित्व रहित आधार पर प्राप्त कर सकते हैं. एक्ज़िम बैंक स्वयं के अलावा भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है. भारत सरकार के आदेश पर जारी ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक माल की शिपिंग पर भारतीय निर्यातकों को संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अपफ्रंट करता है, बशर्ते कि संविदा मूल्य का कम से कम 75 प्रतिशत माल एवं सेवा भारत से लिया जाए. एक्ज़िम बैंक की वर्तमान में 194 ऋण-व्यवस्थाएं परिचालन में हैं जिनके अंतर्गत अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप तथा सीआईएस के 75 देशों में 10.61 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण राशि अलग-अलग क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं के निर्यात वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं.

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के आदेश और सहयोग से अप्रैल-जून 2014 तिमाही के दौरान निम्नलिखित पांच ऋण-व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए हैं :

- नाइजीरिया सरकार को: ट्रान्समिशन लाइनों की आपूर्ति तथा कमिशनिंग, कैदुना राज्य में सौर लघु ग्रिड विद्युतीकरण तथा सौर स्ट्रीट लाइटिंग; तथा नदी-पार राज्य में गैस आधारित बिजली संयंत्र के निर्माण के वित्तपोषण के लिए 100 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था. एक्ज़िम बैंक द्वारा यह ऋण-व्यवस्था भारत सरकार के आदेश पर नाइजीरिया को प्रदान की गयी है.
- मॉरिशस सरकार को: वाटरजेट फास्ट अटैक क्राफ्ट खरीदने के लिए 18 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था. एक्ज़िम बैंक ने इसके पहले मॉरिशस सरकार को ऑफशोर पेट्रोल वेसल तथा विशेषीकृत उपकरणों तथा वाहनों की खरीद के वित्तपोषण के लिए कुल 94.50 मिलियन यूएस डॉलर की दो ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं.
- टोगो गणराज्य सरकार को: दो अतिरिक्त ऋण-व्यवस्थाएं अर्थात 30 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था टोगो में 150 मुहल्लों में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के वित्तपोषण के लिए तथा 52 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था 161 केवी पॉवर ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के लिए प्रदान की गई. एक्ज़िम बैंक ने टोगो को अभी तक कुल 110.10 मिलियन यूएस डॉलर की चार ऋण - व्यवस्थाएं प्रदान की हैं. पहले की 3 ऋण - व्यवस्थाएं ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के वित्तपोषण के लिए और खेती तथा चावल, मक्का एवं सोर्घुम प्रदान की गई हैं.
- कांगो गणराज्य को: केटेन्डे जल विद्युत परियोजना को पूरा करने हेतु वित्तपोषण के लिए कांगो गणराज्य सरकार को 82 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई है. भारत सरकार के निर्देश पर कांगो को एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदान की गई यह पांचवीं ऋण-व्यवस्था है. एक्ज़िम बैंक ने सीमेंट प्लांट की स्थापना, बसों के अर्जन तथा एमआईबीए के लिए उपकरणों के अर्जन, हैंड पम्प तथा सबमर्सिबल पम्प लगाने, काकोबोला जल विद्युत परियोजना और केटेन्डे जल विद्युत परियोजना के निष्पादन के वित्तपोषण के लिए कुल 268.50 मिलियन यूएस डॉलर की चार ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं.

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :
सुश्री गीता पूजारी
महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात आयात बैंक
केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स, कफ़ परेड,
मुंबई : 400 005
फोन :(022) 22172310
फैक्स : (022) 22182460
ई-मेल : eximloc@eximbankindia.in

परियोजना निर्यात : एक्ज़िम बैक की भूमिका

परियोजना निर्यात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के मापदंड होते हैं. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) परियोजना निर्यात के लिए समन्वयकर्ता तथा सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है और समुद्रपारीय टर्न-की औद्योगिक परियोजनाओं, सिविल निर्माण संविदाओं, आपूर्तियों तथा साथ ही तकनीकी एवं परामर्शी सेवा संविदाओं को शामिल करते हुए परियोजना निर्यात पर कार्य दल के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है.

एक्ज़िम बैंक परियोजनाओं के लिए निधिक सहायता, परियोजना से संबंधित गारंटी सुविधाओं तथा अन्य देशों से आयात के प्रति साख पत्र जारी करने सहित भारतीय परियोजना निर्यातकों को एक व्यापक वित्तपोषण पैकेज प्रदान करता है. भारत से परियोजना निर्यात बढ़ाने पर बैंक का जोर भारत सरकार के राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (बीसी-एनईआईए) कार्यक्रम के शुरू होने से बढ़ गया है. यह एक ऐसी वित्तपोषण व्यवस्था है जो भारतीय निर्यातकों को दायित्व-रहित वित्तपोषण विकल्प का एक सुरक्षित तरीका प्रदान करती है और पारंपरिक तथा विकासशील देशों में नए बाजारों, जिन्हें मध्यावधि या दीर्घावधि आधार पर ऋण की जरूरत होती है, के लिए एक प्रभावी बाजार प्रवेश साधन के रूप में कार्य करती है.

यथा 31 मार्च, 2014 को बैंक द्वारा समर्थित कुल ₹1,40,326 करोड़ (लगभग 23.42 बिलियन यूएस डॉलर) मूल्य की 319 परियोजना निर्यात संविदाएं 99 भारतीय कंपनियों द्वारा एशिया, अफ्रीका तथा सीआईएस क्षेत्र के 74 देशों में निष्पादन के अधीन थीं.

मोटर-वाहन (ऑटोमोटिव) उद्योग अर्थव्यवस्था के विभिन्न अन्य खंडों (सेगमेंटों) के साथ मजबूत उत्पादनोत्तर तथा उत्पादन-पूर्व सहबद्धताएं रखता है जो इसे मजबूत तथा सकारात्मक प्रवर्धक प्रभाव प्रदान करते हैं ऑटोमोबाइल को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है-यात्री, वाहन, वाणिज्यिक वाहन, तिपहिया तथा दुपहिया वाहन मात्रा की दृष्टि से दुपहिया वाहन भारत में मोटर वाहन उत्पादन की सबसे बड़ी श्रेणी है जिसका 2013-14 में कुल ऑटोमोबाइल उत्पादन में 78.5 प्रतिशत हिस्सा रहा.

मोटर-वाहन के उत्पादन में 2013-14 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई तथापि यह मुख्यतः दुपहिया वाहनों के उत्पादन के कार्य-निष्पादन के आधार पर था, क्योंकि उन सभी खंडों के उत्पादन में गिरावट आई. वाणिज्यिक वाहन खंड में उत्पादन में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट आई. मोटर-वाहन के बिक्री निष्पादन में भी ऐसी ही प्रवृत्ति देखी गई, सिर्फ दुपहिया खंड में मांग में तेजी पाई गयी.

वाणिज्यिक वाहनों की मांग में 2013-14 में भारी गिरावट आई जिससे बिक्री में तीव्र गिरावट हुई. इसकी मुख्य वजह औद्योगिक खंड में लंबी मंदी, लागत में वृद्धि, निवेश परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब और कुछ राज्यों में खनन कार्य पर प्रतिबंध रहा जिससे वाणिज्यिक वाहनों की मांग प्रभावित हुई. अधिकांश कंपनियों ने भारी डिस्काउंट और उत्पादन में कटौती कर इसका मुकाबला किया.

चालू राजकोषीय वर्ष 2014-15 के दौरान, दुपहिया खंड में बिक्री 2014-15 के दौरान लगभग 2.1 मिलियन यूनिटों के क्षमता परिवर्द्धन के चलते अच्छी गति से बढ़ने की उम्मीद है. इस क्षमता परिवर्द्धन से इन निर्माताओं द्वारा महसूस की जा रही क्षमता बाधाएं कम हो जाएंगी यात्री कार तथा वाहन खंड में, कंपनियां विभिन्न सेगमेंटों में नए मॉडल लाकर और निर्यात बढ़ाने के लिए नए बाजारों में कदम रखकर

चार्ट : ऑटोमोटिव पुर्जाखंड में भारत के प्रमुख भागीदार (2013-14)

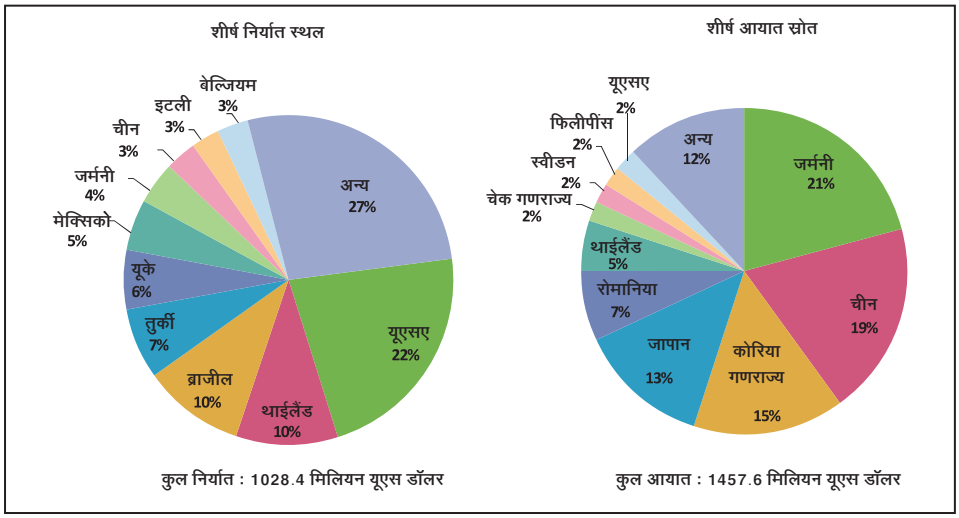

स्रोतः डीजीसीआई एण्ड एस

कार्य-निष्पादन में सुधार लाने पर ध्यान दे रही हैं दूसरी ओर, वाणिज्यिक वाहन खंड में कंपनियों द्वारा स्टॉक के जमाव के कारण क्षमता विस्तार योजनाओं पर धीमी गति से आगे बढ़ने की प्रत्याशा की जाती है.

वर्ष 2013-14 में ऑटोमोबाइल का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 7.2% की दर से बढ़ा है. इसमें मोटर कार तथा सार्वजनिक परिवहन के अन्य वाहनों के निर्यात में अधिकतम वृद्धि हुई (एच एसः 8703; वर्ष-दर-वर्ष 20.5 प्रतिशत की वृद्धि). अफ्रीकी तथा एशियाई देश भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात के लिए महत्वपूर्ण निर्यात स्थान हैं, जबकि भारत के ऑटोमोबाइल आयात का प्रमुख स्रोत यूरोपीय संघ है (चार्ट).

क्षेत्र की निर्यात उन्मुखता 2004-05 के 7.3 प्रतिशत से 2013-14 में 14.5 प्रतिशत हो गई. जो अंतरराष्ट्रीय मांग में अस्थिरता द्वारा प्रभावित दौर में हुई है. यह बढ़ी हुई निर्यात उन्मुखता देश में निर्मित वाहनों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को प्रमाणित करती है. भारत के पास चीन, यूएस, जर्मनी, जापान तथा ब्राजील के बाद छठा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग है. भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या में उछाल न केवल देशी बाजार बल्कि विदेशी बाजारों की जरुरतों को पूरा करने के लिए एक विनिर्माण केन्द्र के रूप में देश की क्षमता का भी प्रमाण है. बढ़ती युवा जनसंख्या और साथ ही बढ़ती आय तथा मध्यम वर्ग की बढ़ती संख्या भविष्य में ऑटोमोबाइल मांग में तेजी लाएगी.

पुरजा उद्योग सीधे ऑटोमोबाइल उद्योग से जुड़ा हुआ है और इसका निष्पादन पुरजा उद्योग में झलकता है यात्री वाहनों तथा वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में गिरावट ने ऑटो पुरजों की माँग को प्रभावित किया परिणामस्वरूप पी बी डी आई टी मार्जिन दिसंबर 2013 तिमाही में 60 आधार बिंदु बढ़ने से लाभप्रदता में सुधार के बावजूद पुरजा निर्माताओं की बिक्री में गिरावट आई लाभप्रदता में यह सुधार मुख्यतः कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के कारण हुआ है. व्यापार मोर्चे पर ऑटोमोबाइल खंड की तरह, ऑटो पुरजों का निर्यात भी 19 प्रतिशत की अच्छी दर से बढ़ा दूसरी ओर आयात 3.8 प्रतिशत की मामूली दर से बढ़ा,ऑटो पुरजों के निर्यात का एक बड़ा अनुपात यूएसए के हिस्से रहा उसके बाद थाईलैंड, ब्राजील, तुर्की और यूके का स्थान रहा.

भारत से ऑटो पुरजों का निर्यात यूरोपीय संघ तथा अमेरिकी बाजारों में निरंतर सुधार के चलते तेजी से बढ़ने की आशा है.

भारत का निर्यात मई में 12.4% बढ़ा

मुंबई : भारतीय निर्यात में पिछले 6 महीने के प्रदर्शन की तुलना में मई 2014 में जोरदार वृद्धि दर्ज की गई. तथापि व्यापार घाटा, निर्यात से आय और आयात खर्च के बीच अंतर, पिछले महीने में 10.1 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर मई में 11.3 बिलियन यू एस डॉलर हो गया. निर्यात मई 2014 में 12.4 प्रतिशत बढ़कर 28 बिलियन यू एस डॉलर हो गया, जबकि आयात 11.4 प्रतिशत घटकर 39.2 बिलियन यू एस डॉलर हो गया. वाणिज्य सचिव राजीव खेर ने कहा कि मई में निर्यात आंकड़ें `उत्साहजनक' हैं. वित्तीय वर्ष 2014-15 के पहले दो महीने अप्रैल-मई में निर्यात 8.9 प्रतिशत बढ़कर 53.6 बिलियन यू एस डॉलर रहा, जबकि इसी अवधि के दौरान आयात 13.2 प्रतिशत घटकर 75 बिलियन यू एस डॉलर रहा. मई में सोने के आयात में 72 प्रतिशत की गिरावट आयी और यह मई 2013 में 7.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2.19 बिलियन यू एस डॉलर रहा.

सरकार ने सोने, चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाया

मुंबई : सरकार ने 30 जून, 2014 को सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर क्रमशः 428 यू एस डॉलर प्रति 10 ग्राम और 688 यू एस डॉलर प्रति किग्रा कर दिया क्योंकि वैश्विक कीमतें भौगोलिक राजनीतिक तनावों के चलते सुरक्षित निवेश खरीदारी पर बढ़ी हैं. जून 2014 के दूसरे पखवाड़े के दौरान आयातित सोने पर प्रशुल्क 411 यू एस डॉलर प्रति 10 ग्राम और चांदी पर 632 यू एस डॉलर प्रति किग्रा था. आयात प्रशुल्क मूल्य वह आधार मूल्य होता है जिस पर अंडर इनवाएसिंग रोकने के लिए सीमा शुल्क का निर्धारण किया जाता है तथा वैश्विक कीमतों में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए इसे पाक्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है. आयातित सोने और चांदी पर प्रशुल्क मूल्य में वृद्धि केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित की गई है. सोने की वैश्विक कीमतें ईराक तथा यूक्रेन में बढ़ते उपद्रवों के कारण मजबूत हुई हैं जिससे इस कीमती धातु की माँग बढ़ गई है. लंदन में सोने की हाजिर कीमत पिछले सप्ताह 1325.9 यू एस डॉलर प्रति औंस के दो महीने के उच्च स्तर पर पहुँच गई. भारत का स्वर्ण आयात चालू खाता घाटे को कम करने के लिए बहुमूल्य धातु के आयात पर सरकार द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण इस वर्ष अप्रैल में 74 प्रतिशत घटकर 1.75 बिलियन यू एस डॉलर रहा.

केन्द्र ने औद्योगिक लाइसेंस की वैधता बढ़ाई

मुंबईः एक प्रेस नोट में सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसों की वैधता अवधि दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी है और कंपनियों द्वारा विस्तार के लिए लाइसेंसिंग समिति के पास वापस जाने की आवश्यकता में ढील दी है. यह विस्तार अब संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के संयुक्त सचिव के अनुमोदन से किया जाएगा. सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 'पहले के सभी प्रेस नोटों के अधिक्रमण में औद्योगिक लाइसेंस की वैधता अवधि कारोबार करने की सुगमता के एक उपाय के रूप में दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष की जा रही है " नए दिशानिर्देश उन मामलों में लागू होंगे जहाँ औद्योगिक लाइसेंस के जारी होने के तीन वर्ष बाद भी, लाइसेंसधारक ने उत्पादन प्रारंभ नहीं किया है. यह नवीकरण दो वर्ष के लिए होगा. विस्तार की पूर्व शर्तों में शामिल हैं: भूमि या तो स्वामित्व के अंतर्गत या न्यूनतम 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर अर्जित कर ली गई हो और परियोजना के लिए संयंत्र एवं मशीनरी के लिए ऑर्डर दे दिए गए हों.

वाणिज्य मंत्रालय ने सेज के लिए कर-लाभ बहाल करने का सुझाव दिया

मुंबई : वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) पर लगाये गए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को वापस लेने का अनुरोध किया है. वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि लेवी ने निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार उत्पन्न करने के एक साधन के रूप में इन क्षेत्रों की संभावना को दबा दिया है. वाणिज्य सचिव राजीव खेर ने कहा, 'हम वित्त मंत्रालय को इस बात से अवगत कराते रहे हैं और हमने मैट तथा डी डी टी को वापस लेने और पहले की स्थिति को बहाल करने के लिए जोरदार सिफारिश की है." उन्होंने कहा कि सेज औद्योगिक विकास, विनिर्माण तथा निर्यात के प्रभावी साधन हैं. इस संभाव्यता को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि 'हम महसूस करते हैं कि सेज के प्रभावी संचालन के लिए इनका संवर्धन आवश्यक है." उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के अनुभव दर्शाते हैं कि 'मैट और डीडीटी के लगाने से निर्यात तथा औद्योगिक विकास के साधन के रूप में सेज की संभाव्यता दब गई है." अतएव हम महसूस करते है कि ये कर समाप्त किए जाने चाहिए, इससे सेज के आस-पास वातावरण उदार बनेगा तथा उद्यमी निवेश करेंगे जिससे विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा.

सरकार ने उत्पादन लाइसेंस वाले रक्षा उत्पादों की सूची तैयार की

दिल्लीः रक्षा विनिर्माताओं को प्रेरित करने की दिशा में एक कदम के रूप में, सरकार ने रक्षा उपकरणों की एक संक्षिप्त सूची प्रकाशित की है जिनके लिए भारत में निर्माण के लिए लाइसेंस जरूरी है.

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी), जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ने उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस की अपेक्षा रखने वाली रक्षा मदों की सूची उल्लिखित करते हुए 2014 का प्रेस नोट सं. 3 जारी किया. इसमें रक्षा उपकरणों की चार श्रेणियां शामिल हैं. जिनके लिए उत्पादन लाइसेंस अनिवार्य है. (क) टैंक तथा अन्य बख्तरबंद युद्ध वाहन (ख) रक्षा विमान, अंतरिक्षयान तथा उनके पुरजे (ग) सभी प्रकार के युद्ध पोत और (घ) शस्त्र एवं गोला-बारूद और रक्षा उपकरणों की सम्बद्ध मदें; उनके पुरजे तथा सहायक पुरजे.

पोचम्पल्ली बुनकरों के लिए उत्पाद विकास कार्यशाला

मुंबईः एक्ज़िम बैंक ने राष्ट्रीय डिजाइन एवं उत्पाद विकास केंद्र (एन सी डी पी डी) के साथ मिलकर मार्च 2014 में पोचम्पल्ली, आंध्रप्रदेश में बुनकरों एवं तकनीशियनों के लिए एक उत्पाद विकास कार्यक्रम का आयोजन किया. एनसीडीपीडी की उद्यमी महिला डिजाइनरों द्वारा दस दिन की इस कार्यशाला में 50 से अधिक बुनकरों, जिनमें 42 महिलाएं थी, को प्रशिक्षित किया गया. इस कार्यशाला का उद्देश्य शिल्पकारों में कौशल का विकास, घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय अवसरों को बढ़ावा देना तथा बुनकरों एवं तकनीशियनों की आजीविका तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाना था. प्रशिक्षण के दौरान इकत डिजाइन वाले उत्पादों (जिसका क्षेत्र के शिल्पकारों द्वारा पारम्परिक रूप से प्रयोग किया जाता है) को आधुनिक ढंग से बनाने का तरीका बताया गया. प्रशिक्षण के दौरान होम फर्निशिंग उत्पाद जैसे पर्दे, मेजपोश, कुशन कवर, यूटिलिटी बॉक्स, टिशू पेपरबॉक्स, फोटो फ्रेम, लेडिज बैग आदि तैयार किए गए. रद्दी सामानों से कई नए उत्पाद जैसे बेल्ट तथा नेकलेस आदि भी डिजाइन किए गए.

भारत-अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आई टी सी के साथ एम ओ यू

मुंबईः भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने आई टी सी के साथ 26 मार्च,2014 को जिनेवा में एक सहमति-ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए, इस सहमति-ज्ञापन से आई टी सी तथा एक्ज़िम बैंक दोनों संस्थाओं के बीच संबंध मजबूत होंगे, इससे उद्यम तथा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिलेगा. आई टी सी तथा एक्ज़िम बैंक अफ्रीका के साथ भारत के व्यापार संबंधों को वरीयता देने की परियोजना को भी सहयोग प्रदान करेंगे जो इस वर्ष से शुरू होकर 2020 तक चलेगी. छह वर्षीय इस परियोजना का उद्देश्य पांच पूर्वी अफ्रीकी देशों ईथियोपिया, केन्या, रवांडा, तंजानिया तथा युगांडा से निवेश तथा भारत की ओर से कौशल अंतरण के माध्यम से भारत को निर्यात बढ़ाने में मद्द करना है.

वित्तीय प्रबंधन में भारत की क्षमता के बारे में ज्ञान तथा जानकारी को बढ़ावा देने के लिए आई सी सी आर के साथ एम ओ यू

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई सी सी आर) ने वित्तीय प्रबंधन में भारत की क्षमता के बारे में ज्ञान तथा जानकारी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वित्तीय प्रबंधन पर लागोस बिजनेस स्कूल, पैन अटलांटिक यूनिवर्सिटी, लागोस, नाइजीरिया में एक आई सी सीआर - एक्ज़िम बैंक पीठ की स्थापना के लिए एक सहमति-ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए जो नाइजीरिया के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने तथा मजबूत करने का कार्य भी करेगा. एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री यदुवेन्द्र माथुर और आई सी सी आर के महानिदेशक श्री सतीश सी. मेहता ने 27 जून, 2014 को नई दिल्ली में इस एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए.

लागोस बिजनेस स्कूल, नाइजीरिया में भारतीय वित्तीय प्रबंधन पर आई सी सी आर - एक्ज़िम बैंक पीठ भारत और नाइजीरिया के बीच द्विपक्षीय सामाजिक आर्थिक सहयोग तथा शैक्षिक संबंधों को मजबूत बनाएगा. ऐसे शैक्षिक तथा बौद्धिक कार्यकलापों का संवर्धन द्विपक्षीय सहयोग का एक अभिन्न पहलू है. इस पीठ की स्थापना से भारत तथा नाइजीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने तथा उसे और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.

पूर्व अफ्रीकी समुदाय पर अध्ययन

मुंबईः एक्ज़िम बैंक ने 'पूर्व अफ्रीकी समुदायः भारतीय व्यापार तथा निवेश संभाव्यता का अध्ययन" पर एक प्रकाशन निकाला. अध्ययन यह दर्शाता है कि ई ए सी क्षेत्र ने हाल के वर्षों में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है. वर्ष 2012 में यह वृद्धि 5.3 प्रतिशत रही. ई ए सी का निर्यात वर्ष 2002 के 2.8 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2012 के दौरान 13.8 बिलियन यू एस डॉलर हो गया है. इसी के अनुरूप ई ए सी का वैश्विक व्यापार भी वर्ष 2002 के 8.9 बिलियन यू एस डॉलर से 5 गुना बढ़कर वर्ष 2012 में 49.3 बिलियन यू एस डॉलर हो गया है अध्ययन इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि हाल के वर्षों में पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के साथ भारत का व्यापार तथा निवेश मजबूत हुआ है. भविष्य में द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के अवसर विद्यमान हैं. भारत तथा पूर्वी अफ्रीका समुदाय के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2002 में 490.8 मिलियन यू एस डॉलर था जो वर्ष 2012 तक 13 गुना बढ़कर 6.6 बिलियन यू एस डॉलर हो गया है. भारत से पूर्व अफ्रीकी समुदाय को निर्यात वर्ष 2002 के 369.3 मिलियन यू एस डॉलर से 16 गुना बढ़कर 2012 में 5.9 बिलियन यू एस डॉलर हो गया है. अध्ययन में पूर्व अफ्रीकी समुदाय के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए रणनीतियां तथा अनुसंशाएं भी दी गई हैं, जिनमें सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है. इनमें परिवहन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्व अफ्रीकी समुदाय में बिजली तथा ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, वित्तीय/बैंकिंग क्षेत्र का विकास; कृषि तथा खाद्य सुरक्षा; क्षमता निर्माण; प्रौद्योगिकी अंतरण तथा मानव संसाधन विकास, आई सी टी तथा ज्ञान का आदान-प्रदान, पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन विकास तथा प्रबंधन; बड़े उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों का विकास; हॉस्पिटलिटी उद्योग, बहुपक्षीय निधिक परियोजनाएं तथा व्यापार संवर्धन संस्थाओं/निवेश संवर्धन एजेंसियों / वाणिज्य मंडल के साथ संस्थागत सहबद्धताएं

वैश्विक क्षेत्र में भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को अभूतपूर्व वृद्धि

टेक्सटाइल उद्योग रोजगार, औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात आय में योगदान की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है. इस दृष्टि से उद्योग का मौजूदा कार्य-निष्पादन अर्थव्यवस्था के लिए विशेष महत्व रखता है. ऐसे समय में जब कई उद्योगों के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) में वृद्धि नकारात्मक हो गई थी, टेक्सटाइल के लिए आई आई पी गत वर्ष की अवधि की तुलना में 4.2 प्रतिशत बढ़ा.

भारत में फाइबर एवं यार्न की अधिकांश श्रेणियों ने फिलामेंट यार्न को छोड़कर 2013-14 के दौरान उत्पादन में वृद्धि दर्ज की. पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न (-6.7 प्रतिशत) और नायलॉन फिलामेंट यार्न (- 0.7 प्रतिशत) के उत्पादन में इस अवधि में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट आयी, जबकि विस्कोस स्टेपल फाइबर (8.4 प्रतिशत) विस्कोस फिलामेंट यार्न (3.3 प्रतिशत) तथा एक्रिलिक स्टेपल फाइबर (32.4 प्रतिशत) का उत्पादन अच्छी गति से बढ़ा. सी एम आई ई के अनुसार, पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर का उत्पादन कॉटन फाइबर और इसके विकल्पी विस्कोस की जोरदार माँग के कारण भी प्रभावित हो सकता है (**चार्ट**).

2013-14 में कपड़े का उत्पादन पावरलूम को छोड़कर सभी श्रेणियों में बढ़ा. कपड़े का कुल उत्पादन 2013-14 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि पावरलूम से उत्पादन में इस अवधि में 1 प्रतिशत की गिरावट आई. तमिल नाडु जहाँ देश में कुल पावरलूम का लगभग 17.2 प्रतिशत है, बिजली की समस्या से जूझ रहा है.

भारतीय टेक्सटाइल निर्यात गत वर्ष की तुलना में

तालिका: वैश्विक टेक्सटाइल निर्यात (मूल्य बिलियन यू एस डॉलर में)

निर्यातक देश	2012	2013	वृद्धि %
चीन	246	274	11.4%
भारत	***33***	***40***	***21.2%***
इटली	34	36	5.9%
जर्मनी	35	35	0.0%
बांग्लादेश	24	28	16.7%
विश्व	**738**	**773**	**4.7%**

स्रोत: एईपीसी

2013 में 21.2 प्रतिशत बढा, जिससे यह 2013 में टेक्सटाइल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया (तालिका). विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 2012 के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 5.2 प्रतिशत हो गया. चीन वैश्विक टेक्सटाइल निर्यात में 35.4 प्रतिशत के हिस्से के साथ सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है.

भारत से परिधान निर्यात भी 2013-14 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 15.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा. रेडीमेड वस्त्रों का भारत से कुल निर्यात में 4.8 प्रतिशत हिस्सा रहा और 2013-14 में भारत से कुल टेक्सटाइल निर्यात का 49.2 प्रतिशत रहा. ऐसे अभूतपूर्व कार्य-निष्पादन का श्रेय कई कारकों को जाता है:

- आर्थिक सुधारों के चलते यू एस तथा ई यू के देशों में उन्नत माँग परिदृश्य.
- परिधान निर्यातक मध्य-पूर्व, लैटिन अमेरिका तथा अफ्रीका में अन्य गैर-पारम्परिक बाजारों में संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं.
- रुपये के मूल्यह्रास ने निर्यातकों को 2013-14 में बेहतर आय प्राप्त करने में सहायता की.
- चीन और बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा में कमी हुई है.
- चीन को उच्च श्रम लागत और डॉलर के मुकाबले युआन की मजबूती का सामना करना पड़ रहा है. बांग्लादेश में श्रम कानूनों से संबंधित चिंताएं अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में फैल गई हैं. देश में न्यूनतम मजदूरी दर में संशोधन की भी उम्मीद हैं.

भारत से टेक्सटाइल निर्यात की संरचना में 2008 से 2012 की अवधि के दौरान थोड़ा परिवर्तन हुआ है, भारत के कुल टेक्सटाइल निर्यात में वस्त्रों (एच एस: 61,62) का हिस्सा पिछले वर्ष के 45 प्रतिशत से घटकर 2012 में 40 प्रतिशत हो गया है. दूसरी ओर अपरिष्कृत कपास, सिल्क और ऊन (एच एस: 50,51,52) का निर्यात जोरदार ढंग से बढ़ा है और 2008 के हिस्से (22 प्रतिशत) की तुलना में 2012 में भारत के टेक्सटाइल निर्यात में 27 प्रतिशत का भारी हिस्सा है.

अनुकूल जनसांख्यिकी, बढ़ती आय और बढ़ते खुदरा क्षेत्र से देशी मांग बढ़ने की उम्मीद है, अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के बाजारों में आर्थिक बहाली से निर्यातकों के ऑर्डर बुक परिदृश्य में और सुधार आने की आशा है. राजकोषीय वर्ष 2013-14 में फैब्रिक निर्माता कंपनियों द्वारा पर्याप्त क्षमता परिवर्द्धन से चालू वर्ष में उत्पादन में वृद्धि में सहायता मिलने की आशा है, इसके अलावा कपास की न्यून कीमतें उद्योग के लिए सहायक सिद्ध होंगी. किंतु बिजली की कमी स्पिनिंग मिलों और फैब्रिक इकाइयों के लिए एक बाधा हो सकती है जो टेक्सटाइल उद्योग के अधिक यंत्रीकृत सेगमेंट हैं. समग्र रूप से, उद्योग के लिए मध्यावधि में संभावना सकारात्मक है.

चार्ट:टेक्सटाईल उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन (2013-14)

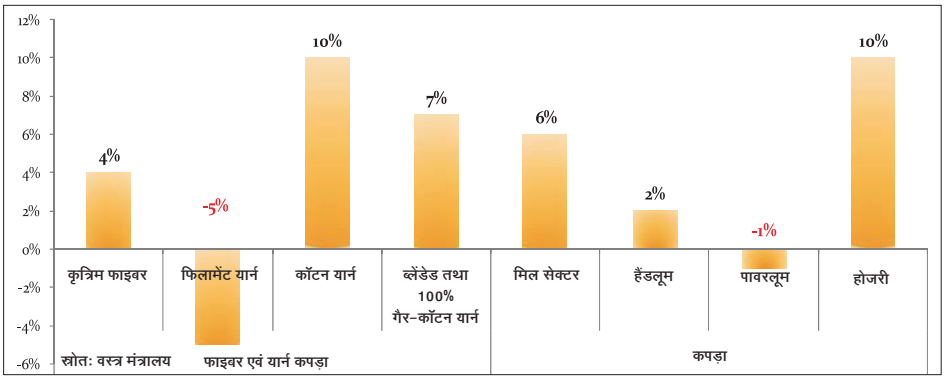

[1] इंडियास्टेट

अफ्रीका में खाद्य एवं कृषि में एफ डी आई

अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2014 के अनुसार, अफ्रीका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) अंतर्वाह 2012 की तुलना में 2013 के दौरान 4 प्रतिशत बढ़कर 57 बिलियन यू एस डॉलर हो गया है.

खाद्य क्षेत्र में एफ डी आई

विनिर्माण क्षेत्र में, खाद्य, पेय तथा तम्बाकू क्षेत्र वर्ष 2013 के दौरान अफ्रीकी क्षेत्र में एफ डी आई अंतर्वाह के लिए एक मुख्य क्षेत्र बना रहा (**तालिका**).

दो उप-क्षेत्रों खाद्य एवं तम्बाकू तथा पेय में से पहले क्षेत्र यानि खाद्य एवं तम्बाकू को वर्ष 2013 से 2014 के दौरान एफ डी आई अंतर्वाह का प्रमुख हिस्सा गया. खाद्य एवं तम्बाकू क्षेत्र ने इस अवधि के दौरान कुल 117,575 रोजगार तथा 18.89 बिलियन यू एस डॉलर के निवेश के साथ सर्वाधिक रोजगार तथा निवेश के अवसर उत्पन्न किए.

अफ्रीकी क्षेत्र में खाद्य क्षेत्र में एफ डी आई प्राप्त करने वाले 40 देशों में से शीर्ष पांच देशों का वर्ष 2003 से 2014 की अवधि के दौरान परियोजनाओं में 2/5 गुणा से अधिक हिस्सा रहा. मिस्र क्षेत्र शीर्ष गंतव्य स्थान है जहाँ प्राप्त की गई परियोजनाओं में इसका 1/10 से अधिक हिस्सा रहा जबकि नाइजीरिया को सर्वाधिक निवेश मिला (**चार्ट**). घाना के पास क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार सृजन दोनों दृष्टियों से औसतन सबसे बड़ा परियोजना आकार रहा.

तालिका : उद्योग द्वारा नई एफ डी आई परियोजनाएं, 2012-13 (मिलियन यू एस डॉलर)

क्षेत्र / उद्योग	गंतव्य स्थान के रूप में अफ्रीका		निवेशकों के रूप में अफ्रीका	
	2012	2013	2012	2013
कुल	**47 455**	**53 596**	**7 764**	**15 807**
प्राथमिक	***7 479***	***5 735***	***455***	***7***
खनन, उत्खनन तथा पेट्रोलियम	7 479	3 795	455	7
	21 129	***13 851***	***4 013***	***7 624***
	2 227	1 234	438	373
टेक्सटाइल, वस्त्र तथा चमड़ा	206	1 750	34	128
गैर - धात्विक खनिज उत्पाद	1 067	3 616	674	2 896
मोटर वाहन तथा अन्य परिवहन उपकरण	2 316	1 593	--	108
सेवाएं	***18 847***	***34 010***	***3 296***	***8 177***

स्रोतः अंकटाड

कृषि में एफ डी आई

कृषि उप-सहारीय अफ्रीका में जी डी पी का औसतन 25 प्रतिशत और अन्य अफ्रीकी देशों में इससे भी अधिक उत्पन्न करती है. विस्तृत कृषि क्षेत्र का जी डी पी में आधा हिस्सा अनुमानित है.

कृषि में एफ डी आई निवेश उत्पाद तथा क्षेत्र के अनुसार भिन्न-भिन्न है. मुख्य फसलों जैसे चावल में एफ डी आई सामान्यतः कम है और नकदी फसलों जैसे पुष्पकृषि या चीनी में अधिक है. अफ्रीका को मुख्य फसलों जैसे चावल, गेहूँ तथा तिलहन फसलों में अच्छा एफ डी आई मिल रहा है जबकि पूर्व अफ्रीका में पुष्प कृषि के क्षेत्र में एफ डी आई आ रहा है, तथापि अफ्रीका के एफ डी आई आवक में कृषि का हिस्सा लैटिन अमेरिका के 15 प्रतिशत तथा एशिया के 78 प्रतिशत की तुलना में सिर्फ 7 प्रतिशत रहा है.

अफ्रीका के कृषि व्यवसाय बाजारों में एफडीआई का बड़ा हिस्सा आकृष्ट करने की अच्छी संभावना है और निवेशकों में अफ्रीका के कृषि कारोबार बाजारों में रुचि बढ़ रही है. सुज्ञात जोखिमों के बावजूद, अफ्रीका में कृषि क्षेत्र में दो महत्त्वपूर्ण अवसर है अकृष भूमि की विशाल मात्रा (वैश्विक उपलब्धता की आधे से अधिक) तथा जल संसाधन मैकिंसी के अनुमानों के अनुसार वर्ष अफ्रीकी कृषि उत्पादन वर्ष 2010 के 280 बिलियन यू एस डॉलर से 2020 तक लगभग दुगुना होकर 500 बिलियन यू एस डॉलर (क्षेत्र के जीडीपी का 40%) और 2030 में 880 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर तक पहुँच सकता है, अकृष भूमि के भारी क्षेत्रफल के साथ तटीय देश इस वृद्धि संभाव्यता में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं. इनमें अंगोला, कैमरून, कोत दि वॉर, ईथियोपिया, घाना, केन्या, मैडागॉस्कर, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, सूडान तथा तंजानिया शामिल हैं. अकेले नाइजीरिया द्वारा 2014 में कृषि में लगभग 1.5 बिलियन यू एस डॉलर का विदेशी तथा देशी निवेश आकृष्ट किए जाने की उम्मीद है.

चार्ट: वर्ष तथा गंतव्य देश के अनुसार एफ डी आई परियोजनाओं की संख्या

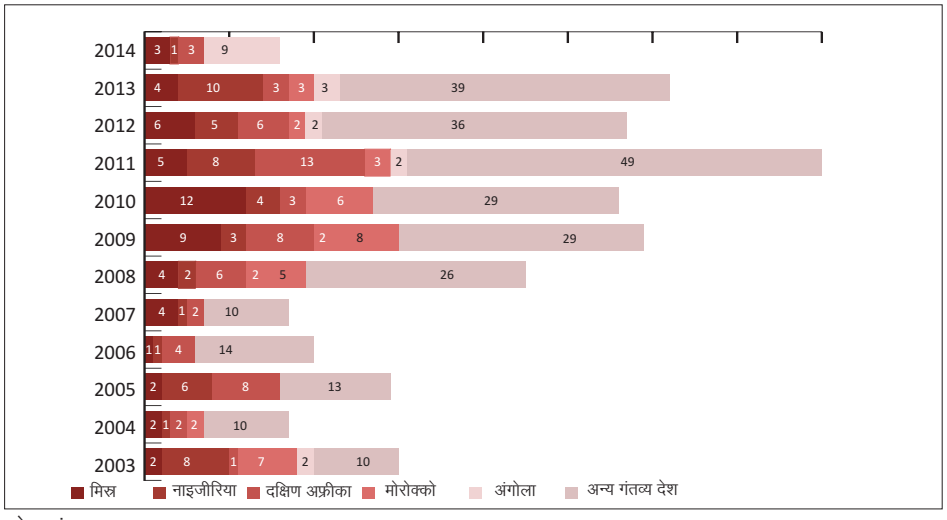

स्रोतःअंकटाड

एक्ज़िम बैंक कार्यकलाप तथा साहित्य समीक्षा

विपणन सलाहकारी सेवाएं
अप्रैल - जून 2014

एक्ज़िम बैंक अपनी विपणन सलाहकारी सेवाओं के जरिए भारतीय कंपनियों में निर्यात क्षमता सृजित करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. एक्ज़िम बैंक भारतीय फर्मों के उत्पादों एवं सेवाओं के लिए विदेशी-क्रेताओं तथा विक्रेताओं की पहचान करने के साथ-साथ उनके वैश्वीकरण प्रयासों में मदद करता है.

एक्ज़िम बैंक ने राष्ट्रीय डिजाइन एवं उत्पाद विकास केन्द्र के साथ मिलकर पोचम्पल्ली के बुनकरों के लिए उत्पाद विकास कार्यशाला में डिजाइन किए गए विभिन्न प्रकार के गृह-सज्जा तथा अन्य सहायक उत्पादों को विकसित करने के लिए पोचम्पल्ली हैंडलूम पार्क लि. (पी एच पी एल) की मदद की है. इस प्रयास को और आगे बढ़ाने के लिए एक्ज़िम बैंक ने भी पी एच पी एल की मदद की है. हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित व्यापार मेला आधुनिक घर की सभी जरूरतों जैसे होम फर्नीचर, घर-सज्जा, सजावटी और घरेलू उत्पाद जैसे किचनवेयर, टेबलवेयर, गार्डन वेयर, बाथरूम के सामान आदि को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने संबंधी एक विशाल प्रदर्शनी थी.

होम एक्सपो इंडिया 2014 में पी एच पी एल के बूथ को प्रायोजित करने का उद्देश्य नए बाजार अवसरों की खोज करना और बड़ी संख्या में देशी तथा विदेशी क्रेताओं तक पहुँचना था. चार दिन की प्रदर्शनी के दौरान 300 से अधिक व्यक्तियों और विदेशी लाइफस्टाइल स्टोरों, स्पेशियालिटी स्टोरों, रिटेलरों, आंतरिक डिजाइनरों, ऑनलाइन रिटेलरों, आयातकों तथा क्रय एजेंटों से 50 से अधिक प्रतिनिधि पी एच पी एल के बूथ पर पधारे. इसके फलस्वरूप विदेशी तथा घरेलू बाजारों से कई क्वेरीज प्राप्त हुई.

एक्ज़िम बैंक ने भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि. (सी सी आई सी) के साथ मिलकर पी एच पी एल तथा अनवर अली जूट क्राफ्टस एंड बैग्स को नई दिल्ली में सी सी आई सी के कॉटेज एम्पोरियम में आठ दिन 'प्रदर्शनी एवं बिक्री' कार्यक्रम में भाग लेने में उनकी सहायता की. प्रदर्शनी में होम तथा बेड फर्नीशिंग एवं सहायक उत्पाद, रेडीमेड वस्त्र, पोचम्पल्ली टेक्सटाइल फैब्रिक्स और जूट से बनाए गए कॉरपोरेट यूटिलिटी एवं फैशन उत्पाद प्रदर्शित किए गए. इस प्रदर्शनी सह-बिक्री कार्यक्रम में दोनों प्रतिभागियों ने कई विदेशी तथा स्थानीय क्रेताओं को आकर्षित किया. पी.एच.पी.एल तथा अनवर अली ने क्रमशः ₹1.2 लाख और ₹ 20,000/- के जूट उत्पादों की बिक्री की.

एक्ज़िम बैंक अपनी विपणन सलाहकारी सेवाओं के जरिए भारतीय कंपनियों में निर्यात क्षमता सृजित करने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में संवर्धनात्मक भूमिका अदा करता है. एक्ज़िम बैंक भारतीय निर्यात फर्मों के उत्पादों एवं सेवाओं के विदेशों में वितरकों/क्रेताओं /भागीदारों की पहचान करने के साथ-साथ उनके लिए व्यवसाय अवसर तलाशने और उनके वैश्वीकरण प्रयासों में मदद करता है.

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप महाप्रबंधक

भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई

फोन नं. : (022) 22172829

ई-मेल : deepali@eximbankindia.in

गाइड टु इमर्जिंग मार्केट्स –बिजनेस आउटलुक, अपार्चुनिटीज एंड ऑवस्टेकल्स – दि इकोनॉमिस्ट

इकोनॉमिस्ट कॉरपोरेट नेटवर्क टीम का यह प्रकाशन कारोबारी चुनौतियों का सामना करने, अवसरों का पता लगाने जोखिमों का प्रबंध तथा उन्हें कम करने और सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं इस संबंध में प्रकाश डालता है. इस प्रकाशन को दो भागों में बाँटा गया है - पहला भाग उभरते बाजार में व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोणों, उद्यमियों की सोच, अंतर्निहित विभिन्न जोखिमों और सही दृष्टिकोण अपनाने पर केन्द्रित है. दूसरा भाग ब्रिक देशों (ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन) से लेकर पूर्वी यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका की उभरती अर्थव्यवस्थाओं तक विभिन्न बाजारों की समीक्षा करते हुए फर्मों को उभरते बाजारों को प्राथमिकता देने में सहायता पर केन्द्रित है.

यह प्रकाशन उभरते बाजारों की वृद्धि की उत्प्रेरक प्रवृत्तियों की जाँच करता है और यह विचार देता है कि उभरते बाजार भविष्य में कैसे चल सकते हैं. यह इस पर भी प्रकाश डालता है कि उभरते बाजार कारोबारी अवसर की दृष्टि से किस सीमा तक एक ही प्रकार के हैं. अध्ययन अवसरों की पहचान करने में बाजार अनुसंधान की भूमिका को भी रेखांकित करता है.

इकोनॉमिस्ट कॉरपोरेट नेटवर्क टीम द्वारा तमाम वर्षों में हासिल विशेषज्ञता और सैकड़ों कंपनियों में उनके द्वारा कार्य करने से अर्जित ज्ञान का उपयोग करते हुए यह प्रकाशन उभरते बाजारों में विद्यमान अवसरों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए और उनका लाभ उठाने के लिए एक सर्वोत्तम गाइड है.

नाइजीरिया

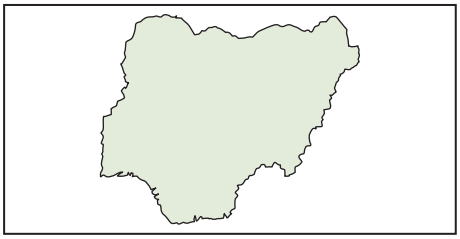

नाइजीरिया भारी जीडीपी के साथ अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से आगे निकल गया है. यह अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और तेल इसके राजकोषीय राजस्व का 80 प्रतिशत तथा उसकी निर्यात आय का 95 प्रतिशत है. तेल निर्यात पर उच्च निर्भरता देश को वैश्विक अस्थिरता के जोखिम में डालती है. इसके अलावा, आर्थिक नीति निर्णय में पारदर्शिता का अभाव, भ्रष्टाचार का उच्च स्तर, संरचनागत सुधार के लिए सीमित राजनीतिक इच्छा और क्षमता ने कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते जोखिमों को तीव्र कर दिया, 2015 के चुनावों की अवधि में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता निवेशकों के विश्वास को प्रभावित कर सकती है और उच्चतर वृद्धि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर नीतिगत अड़चनों का समाधान करने में सरकार को रोक सकती है.

तुर्की

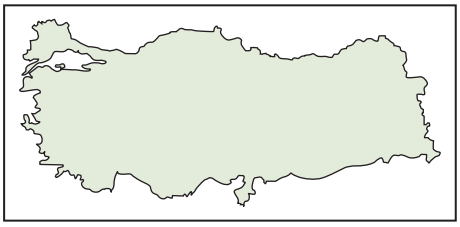

वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर घरेलू खर्च में वृद्धि तथा माल एवं सेवाओं की सार्वजनिक क्षेत्र में जोरदार खपत और स्थिर निवेश की बदौलत 2012 में 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 4.3 प्रतिशत के अनुमानित स्तर पर पहुँच गई. यह निवल निर्यात से आर्थिक वृद्धि दर एक भारी अड़चन (ड्रैग) को समंजित करता है क्योंकि मजबूत देशी माँग ने माल तथा सेवाओं के उच्चतर आयात को बढ़ावा दिया और निर्यात वृद्धि मंद रही. मुद्रा कमजोरी के आवर्ती दौर ने उपभोक्ता मुद्रास्फीति को केन्द्रीय बैंक के 5 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर रखा है. अनुमान है कि वृद्धि दर 2015 मध्य तक मंद रहेगी. जबकि चालू खाता घाटा बहुत उच्च रहेगा. सरकार विरोधी प्रतिरोध और बढ़ते भ्रष्टाचार घोटालों और साथ ही तुर्की की दक्षिणी सीमा पर सीरियाई नागरिक युद्ध ने तुर्की में अस्थिरता को बढ़ावा दिया है.

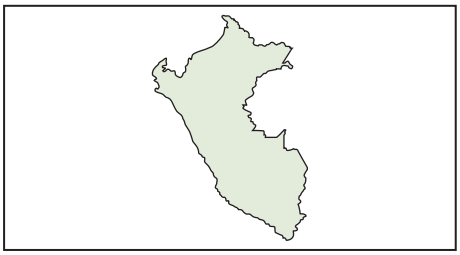

पेरू

पेरू की अर्थव्यवस्था 2013 में 5 प्रतिशत की अनुमानित दर से बढ़ी जो 2012 के 6.3 प्रतिशत से कम है. धीमी वृद्धि अंशतः धातुओं जिनका पेरू के कुल निर्यात में आधे से अधिक योगदान होता है, की कीमतों में नरमी के कारण है. पेरू अन्य धातुओं के साथ तांबा, सोना, चांदी और जिंक का एक प्रमुख वैश्विक उत्पादक है, जहाँ खनन कंपनियां खनिज संपन्न भंडारों को विकसित करने के लिए करोड़ों बिलियन डॉलर निवेश कर रही हैं. पेरू ने 2012 की तुलना में 2013 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट दर्ज की, फिर भी निवेशकों के लिए यह अब भी एक आकर्षक बाजार बना हुआ है 2013 में पेरू ने तांबे और सोने की कम कीमतों, जिनसे निर्यात आय प्रभावित हुई, के चलते एक दशक से अधिक समय के बाद पहली बार व्यापार घाटा दर्ज किया. पेरू के राष्ट्रीय सांख्यिकीय संस्थान के अनुसार खनन तथा विनिर्माण कार्यकलापों में गिरावट के परिणामस्वरूप पेरू की अर्थव्यवस्था ने पहली तिमाही के दौरान मंद वृद्धि (चौथी तिमाही में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 4.8 प्रतिशत) दर्ज हुई.

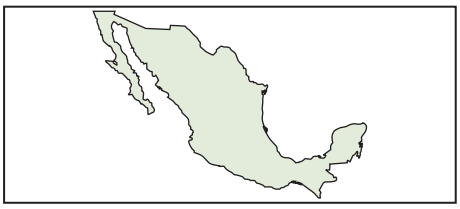

मेक्सिको

मेक्सिको लैटिन अमेरिका में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. मेक्सिको एक प्रमुख तेल उत्पादक तथा निर्यातक भी है, जिसके अधिकांश कच्चे तेल की खरीद अमेरिका द्वारा की जाती है. अर्थव्यवस्था कमजोर देशी तथा विदेशी मांग के चलते 2013 में 1.3 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ी जो 2009 की मंदी के बाद से न्यूनतम दर है. इसके अलावा तेल के निर्यात और उत्पादन में 2014 की पहली तिमाही में गिरावट आयी जिससे मेक्सिको को अमेरिका से उसके द्वारा निर्यातित पेट्रोलियम उत्पादों से अधिक पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के लिए बाध्य होना पड़ा. मेक्सिको को अपने निर्यात आधारित विनिर्माण क्षेत्र, जिसे पिछले दो वर्षों में काफी कमजोर पेसो से लाभ हुआ, की गतिशीलता, औसत से अधिक उत्पादकता और चीन की तुलना में बढ़ती मजदूरी प्रतिस्पर्धात्मकता से लाभ होने की उम्मीद है.

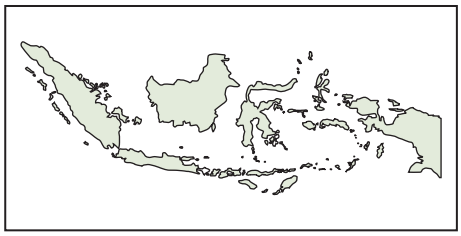

इंडोनेशिया

जीडीपी वृद्धि दर पिछले तीन वर्षों के दौरान 6.3 प्रतिशत के औसत से घटकर 2013 में 5.8 प्रतिशत रही क्योंकि निवेशों में तीव्र गिरावट आयी. केंद्रीय बैंक ने बढ़ती मुद्रास्फीति और बढ़ते चालू खाता घाटे को देखते हुए देशी मांग को नियंत्रित रखने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की. नियत निवेश में वृद्धि 2010-2012 में लगभग 9 प्रतिशत वार्षिक की जोरदार वृद्धि के बाद 2013 में घटकर 4.7 प्रतिशत रही, जो निवेशों पर उच्चतर बाज दरों और रुपया के मूल्यह्रास का प्रभाव दर्शाता है. खराब मौसम और पॉम ऑयल तथा रबड़ की गिरती कीमतों ने कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर गिरकर 3.5 प्रतिशत पर पहुँचा दीं. खनन उत्पादन सिर्फ 1.3 प्रतिशत बढ़ा जो कोयले तथा धातु में वृद्धि किंतु तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन में संकुचन दर्शाता है. राजकोषीय नीति ने कुछ समर्थन प्रदान किया किन्तु अर्थव्-यवस्था में मंदी ने राजकोषीय घाटा 2012 में 1.9 प्रतिशत की तुलना में 2013 में जीडीपी का 2.3 प्रतिशत हो गया. सामाजिक नीतियों पर सरकारी खर्च बढ़ा जबकि कर राजस्व निर्यात पण्यों की कीमतों में गिरावट और कमजोर आयात के चलते घटा.

मुद्रा की प्रवृत्तियां

येन

जापानी येन (जे पी वाई) यूएस डॉलर तथा यूरो के बाद सबसे मजबूत विदेशी मुद्रा है. इसे यूएस डॉलर, यूरो तथा पाउंड स्टर्लिंग के बाद रिज़र्व मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

जापानी येन में जून के अंतिम सप्ताह के दौरान मजबूती रही, क्योंकि यह 101-102 के दायरे में हो रहा था. बैंक ऑफ़ जापान के गवर्नर हारुहिको कुरोडा ने कहा कि केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीतियों से आर्थिक वृद्धि हुई है, लेकिन मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं.

पिछले तीन महीने में जापानी येन कठोर दायरे (रेंज) में रहा है, किंतु कठोर दायरे के भीतर सतत मजबूती यह दर्शाती है कि ब्रेकआउट अपरिहार्य है, जापानी मुद्रा काफी समय से स्थिर रही है और हर कोई इस बात का कयास लगा रहा है कि आखिर येन अपने हाल के रेंज को कब तोड़ सकता है. तथापि यह एक आधारभूत उत्प्रेरक होने जा रहा है जो यह आगामी जापानी सीपीआई को मुद्रास्फीति आंकड़ों पर खरा उतर सकता है. एक मूल प्रश्न यह रह जाता है कि क्या बैंक ऑफ़ जापान अपने आक्रामक मात्रात्मक सरलीकरण उपायों को बढ़ावा देना जारी रखेगा ?

बैंक ऑफ़ जापान के गवर्नर कुरोडा ने इस बात पर जोर दिया है कि केन्द्रीय बैंक अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है और मौद्रिक नीतिगत प्रोत्साहनों को वापस लेने की बात असामयिक है वस्तुतः सीपीआई मुद्रास्फीति में अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकता है जिसका येन पर भारी प्रभाव पड़ सकती है. यूएस डॉलर - जापानी येन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अपरिहार्य है और वस्तुतः बाजार अल्पकालिक ट्रेडिंग के माध्यम से इसकी आशा कर रहा है. किन्तु फोकस अभी भी आगामी जापानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़ों के आधार पर बैंक ऑफ जापान के नीतिगत निर्णयों पर है. जापानी येन 30 जून, 2014 को 1 यू एस डॉलर = 101.23 जापानी येन पर उद्धृत हो रहा था.

भारतीय रुपया

भारतीय रुपये की विनिमय दर बाजार निर्धारित है. तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक विनिमय दरों को नियंत्रित करने के लिए यूएस डॉलर / भारतीय रुपया मुद्रा बाजार में सक्रिय रूप से ट्रेड करता है.

भारतीय रुपया 23 मई, 2014 को 58.33 के ग्यारह महीने के उच्च स्तर पर पहुँचने के बाद कमजोर देशी बाजार और ईराक में तनाव के कारण कमजोर वैश्विक बाजार के कारण कमजोर हुआ. हालांकि रिज़र्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के बयान से बाजार को आश्वासन मिला जिसमें उन्होंने कहा कि देश-जारी ईराकी तनावों, जिनसे मुद्रा में नकारात्मक उतार-चढ़ाव आया, जैसे बाह्य आघातों से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार है.

अगले एक वर्ष में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के 63 पर ट्रेड किए जाने की उम्मीद है. यह पूर्वानुमान अंशत वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान भारत के चालू खातो घाटा (कैड) में वृध्दि पर आधारित है. बेहतर घरेलू माँग के चलते आयात में क्रमिक वृद्धि और नई सरकार द्वारा सोने के आयात पर प्रतिबंध में कुछ छूट के कारण 2014-15 में कैड क्रमिक रूप से बढकर जीडीपी का 2.6 प्रतिशत हो जाएगा. रुपया 30 जून, 2014 को1 यूएस डॉलर = 60.08 भारतीय रुपये पर उध्दृत हो रहा था.

रूसी रूबल

रूसी रूबल (आर यू बी) उस स्तर पर वापस पहुँच गया है जहां यह रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के हटाने से 22 फरवरी, 2014 को शुरू हुए यूक्रेन संकट से पूर्व था. रूबल 14 मार्च, 2014 को 36.65 के स्तर तक पहुँच गया था और तभी से मजबूत हो रहा है और अब डॉलर के मुकाबले 33.83 है. यह वर्ष की शुरूआत से 2.99 प्रतिशत नीचे है. रूसी मुद्रा यूक्रेन में स्थिति से उत्पन्न भौगोलिक जोखिमों द्वारा उत्प्रेरित पहले की हानियों को वापस पूरा कर रही है. निवेशकों में विश्वास है कि यूक्रेन संबंधित दबाव धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं.

इस बीच रूस के केन्द्रीय बैंक ने रूबल के लिए अपने समर्थन को कम करना जारी रखा है जो यह संकेत देता है कि अगले वर्ष के प्रारंभ से मुद्रा के मुक्त रूप से होने की उसकी योजना पटरी पर है. नीति निर्माताओं में यह विश्वास पुख्ता हुआ है के रूसी बाजार यूक्रेन पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद स्थिर हो गया है. तदनुसार केन्द्रीय बैंक ने 17 जून, 2014 को घोषणा के लिए मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेपों की मात्रा को कम किया है, जो मुद्रास्फीति को अधिक महत्वपूर्ण आधार बनाने की दिशा में दीर्घकालिक नीति का संकेत है.

योजना के अनुसार रूबल का ट्रेडिंग कॉरिडोर अगले वर्ष जनवरी से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और नियमित दैनिक हस्तक्षेप बंद हो जाएगा. यद्यपि बैंक वित्तीय स्थिरता के लिए विवेकपूर्ण हस्तक्षेप करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखेगा. 30 जून, 2014 को 1 यू एस डॉलर = 33.98 रूबल पर उध्दृत हो रहा था.

एक्ज़िम बैंक के कार्य-निष्पादन की विशेषताएं - 2013–14

वित्तीय तथा कारोबारी कार्य–निष्पादन

- बैंक का कर पूर्व लाभ तथा कर पश्चात लाभ 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 10.20 बिलियन और ₹ 7.10 बिलियन रहा.
- ₹ 3.39 बिलियन की राशि एक्ज़िम बैंक अधिनियम के अनुसार पूंजी पर प्रतिफल के रूप में केंद्र सरकार को अंतरित की गई.
- जोखिम परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सी आर ए आर) 14.32 प्रतिशत रहा, निवल ऋण आत्तियों की तुलना में निवल एन पी ए 31 मार्च, 2014 को 0.43 प्रतिशत रहा.
- बैंक की निवल संपत्ति 31 मार्च 2014 को बढ़कर ₹ 83.10 बिलियन हो गई.
- वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 35 देशों को शामिल करते हुए ₹ 341.31 बिलियन मूल्य की 75 परियोजना निर्यात संविदाएं 40 भारतीय निर्यातकों द्वारा प्राप्त की गई.
- बैंक ने क्रेता ऋण राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (बी सी - एन ई आई ए) के अंतर्गत 520 मिलियन यू एस डॉलर मूल्य की 5 परियोजनाओं के लिए कुल 444 मिलियन यू एस डॉलर की राशि मंजूर की है.
- वर्ष के दौरान बैंक ने भारत से परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं के निर्यात को समर्थन देने के लिए कुल ₹1,771.75 मिलियन यू एस डॉलर मूल्य की 24 नई ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं.
- 37 देशों में समुद्रपारीय निवेशों के आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल ₹ 64.66 बिलियन की निधिक और गैर-निधिक सहायता के साथ वर्ष के दौरान 42 समुद्रपारीय उद्यम मंजूर किए गए.
- 2013-14 में बैंक को भारत सरकार से ₹ 7 बिलियन की पूंजी प्राप्त हुई.
- वर्ष के दौरान, बैंक ने विभिन्न परिपक्वता अवधियों की उधार राशियां जुटाई जिसमें ₹ 226.54 बिलियन के रुपया संसाधन और ₹ 192.38 बिलियन के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन शामिल थे.
- यथा 31 मार्च, 2014 को कुल उधार राशियां ₹ 714.82 बिलियन रहीं जिसमें बाजार उधारियां बैंक के कुल संसाधनों का 100 प्रतिशत रही.

नई पहलें

- एक्ज़िम बैंक अफ्रीका में एक परियोजना विकास कंपनी (पीडीसी) की स्थापना करेगा. यह कंपनी अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को बैंक ग्राह्य स्तर तक लाने में मदद करेगी तथा अफ्रीका को भारतीय निर्यात बढ़ाने में मदद करेगी.
- बैंक ने यांगून, म्यांमार में अपना आठवा प्रतिनिधि कार्यालय खोला है सरकारी स्वामित्व में म्यांमार में अपने परिचालन स्थापित करने वाला विश्व का पहला एक्ज़िम बैंक है.
- बैंक ने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. (एन एच डी सी) और एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेशन्स एंड अपेक्स सोसायटीज ऑफ हैंडलूम्स (एसीएएसएच) के सहयोग से एक नई संयुक्त उद्यम यानि भारत हैंडलूम मार्केटिंग कंपनी (बी एच एम सी एल) का गठन किया.
- बैंक ने समसामयिक पत्रों और कर्यशील पत्र (वर्किंग पेपर) के रूप में वर्ष 2013-14 के दौरान 15 शोध पत्र प्रकाशित किए.

सूचना एवं सलाहकारी सेवाएं

- बैंक ने विश्व बैंक समूह तथा अफ्रीकी विकास बैंक समूह द्वारा निधिक परियोजनाओं में कारोबारी अवसर पर नई दिल्ली, मुंबई तथा हैदराबाद में चर्चा परक सेमिनारों का आयोजन किया.
- बैंक को श्री लंका में समग्र निर्यात वित्तपोषण ढांचे को बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश करते हुए परिचालन नीतियों की समीक्षा करने और अन्य उत्पाद सुझाने के लिए श्री लंका निर्यात ऋण बीमा निगम (एस एल ई सी आई सी) की सहायता करने के लिए राष्ट्रमंडल सचिवालय (कॉमसेक) लंदन द्वारा अधिकृत किया गया है.
- एक्ज़िम बैंक ने आई टी सी, जिनेवा के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय निर्यात रणनीति विकसित करने के लिए म्यांमार सरकार के लिए परामर्श मिशन का कार्य हाथ में लिया.
- वर्ष के दौरान, रेडीमेड वस्त्रों, एफ एम सी जी उत्पादों और हैंडीक्राफ्ट के लिए देशी तथा विदेशी बाजारों से 80 आदेश प्राप्त किए गए.

कार्यशालाएं

वर्ष के दौरान बैंक ने शिल्पकारों को प्रशिक्षित करने के लिए असम, आंध्र प्रदेश कर्नाटक तथा त्रिपुरा में कई कार्यशालाएं आयोजित की.

संस्थागत सहबद्धताएं

- ब्रिक्स देश पहल के अंतर्गत दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए; अफ्रीका के लिए ब्रिक्स बहुपक्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर सह-वित्तपोषण; और सतत विकास हेतु ब्रिक्स बहुपक्षीय सहयोग एवं सह - वित्तपोषण करार.
- बैंक ने यूके व्यापार एवं निवेश (यू के टी आई) भारतीय लघु एवं मध्यम कारोबार विकास मंडल (भारतीय एस एम ई मंडल), विश्वेस्वरैया व्यापार संवर्धन केंद्र (वी टी पी सी) सहित कई संस्थाओं के साथ सहयोग ज्ञापन / सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और साथ ही वूमन ऑन विंग्स नीदरलैंड; राष्ट्रीय डिज़ाइन एवं उत्पाद विकास केन्द्र (एन सी डी पी डी) विश्व शिल्प परिषद, (डब्ल्यू सी सी) और अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आई टी सी) जिनेवा के साथ सहयोग करार पर भी हस्ताक्षर किए.
- एक्ज़िम बैंक ने भारतीय उद्योग मंडल के साथ मिलकर नई दिल्ली में भारत अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 10 वें सी आई आई एक्ज़िम बैंक महासम्मेलन का आयोजन किए.
- एक्ज़िम बैंक नवंबर 2014 के दौरान अट्ठाइसवें एशियाई एक्ज़िम बैंक मंच की मेजबानी करेगा. तकनीकी कार्य-समूह (टी डब्ल्यू जी) की बैठक नई दिल्ली में मार्च 2014 के दौरान आयोजित की गई.

भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य

संकेतक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
जीडीपी (वर्तमान मूल्यों पर, बिलियन यूएस डॉलर)	1224.1	1365.4	1708.5	1880.3	1858.7	1877.5[e]	2134.7[f]
प्रति व्यक्ति जीडीपी (यू एस डॉलर)	1044.9	1146.7	1411.7	1528.7	1486.8	1472.1[e]	-
वास्तविक जीडीपी वृद्धि (%)	6.7	8.6	8.9	6.7	4.5	4.7[e]	6.0[f]
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	0.1	0.8	8.6	5.0	1.4	4.7[e]	-
उद्योग	4.4	9.2	7.6	7.8	1.0	0.4[e]	-
सेवाएं	10.0	10.5	9.7	6.6	7.0	6.8[e]	-
जीडीपी में क्षेत्रगत हिस्सा (%)							-
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	15.8	14.6	14.6	14.4	13.9	14.0[e]	-
उद्योग	28.1	28.3	27.9	28.2	27.3	26.1[e]	-
सेवाएं	56.1	57.1	57.5	57.4	58.8	59.9[e]	-
जनसंख्या (मिलियन)	1171.5	1190.7	1210.2	1230.0	1250.2	1270.6[e]	-
मुद्रास्फीति की दर (डब्ल्यूपीआई, वार्षिक औसत %)	8.1	3.8	9.6	8.9	7.4	6.0	5.43 (जून80 '14)
सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	6.0	6.5	4.8	5.7	4.9	4.5	4.1[e]
विनिमय दर (₹. / यूएस डॉलर, औसत)	45.9	47.4	45.6	47.9	54.4	60.5	60.09 (जून 30,'14)
विनिमय दर (₹. / यूरो, औसत)	65.1	67.1	60.2	65.9	70.1	81.2	82.01 (जून 30,'14)
निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	185.3	178.8	251.1	306.0	300.4	314.4	78.6 (एप्रिल-जून)
% परिवर्तन	13.6	-3.5	40.5	21.8	-1.8	4.7	7.0^
तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	27.5	28.2	41.5	56.0	60.9	63.2	15.8 (एप्रिल-जून)
% परिवर्तन	-3.0	2.3	47.2	34.9	8.7	3.8	11.3^
गैर-तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	157.7	150.6	209.6	250.0	239.5	251.2	62.8 (अप्रैल-जून)
% परिवर्तन	17.1	-4.6	39.2	19.3	-4.2	4.9	6.0^
आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	303.7	288.4	369.8	489.3	490.7	450.2	113.1 (अप्रैल-जून)
% परिवर्तन	20.7	-5.1	28.2	32.3	0.3	-8.3	-6.4^
तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	93.7	87.1	106.0	155.0	164.0	164.8	34.6 (अप्रैल-जून)
% परिवर्तन	17.4	-7.0	21.6	46.2	5.9	0.4	-11.2^
गैर-तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	210.0	201.2	263.8	334.3	326.7	285.4	78.5 (अप्रैल-जून)
% परिवर्तन	22.2	-4.2	31.1	26.7	-2.3	-12.6	-4.2^
व्यापार शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	-118.4	-109.6	-118.7	-183.3	-190.3	-135.8	-34.5 (अप्रैल-जून)
सेवा निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)**	106.0	96.0	124.6	142.3	145.7	151.5	27.6 (अप्रैल-मे)
सॉफ्टवेयर निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)**	46.3	49.7	53.1	62.2	65.9	69.5	-
सेवा आयात (बिलियन यूएस डॉलर)**	52.0	60.0	80.6	78.2	80.8	78.5	16.1 (अप्रैल-मई)
सेवा शेष (बिलियन यूएस डॉलर)**	54.0	36.0	44.0	64.1	64.9	73.0	11.5 (अप्रैल-मई)
चालू खाता शेष (बिलियन यूएस डॉलर)**	-28.7	-38.4	-47.9	-78.2	-87.8	-32.4	-
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष (%)	-2.3	-2.8	-2.8	-4.2	-4.8	-1.7	-
विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन यूएस डॉलर)	252.0	279.1	304.8	294.4	292.0	304.2	315.8 (जून 27,'14)
विदेशी ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	224.5	260.9	317.9	360.8	409.4	440.6	-
जीडीपी की तुलना में विदेशी ऋण अनुपात (%)	20.3	18.2	18.2	20.5	22.0	23.3	-
अल्पावधि ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	43.3	52.3	65.0	78.2	96.7	89.2	-
अल्पावधि ऋण / कुल ऋण (%)	19.2	20.1	20.4	21.7	23.6	20.3	-
कुल ऋण चुकौती अनुपात (%)	4.4	5.8	4.4	6.0	5.9	5.9	-
एफडीआई (बिलियन यूएस डॉलर)	41.9	37.7	34.8	46.6	34.3	36.0	11.1 (Apr-Jun)
	1.2	3.3	2.0	0.6	0.2	0.02	-
	-15.0	29.0	29.4	16.8	27.6	5.0	12.5 (अप्रैल-जून)
	19.4	15.1	16.5	10.9	7.1	9.2	-0.04 (अप्रैल-जून)
मेमो मदें :	2009	2010	2011	2012	2013	2014[f]	2015[f]
वैश्विक जीडीपी (% परिवर्तन)	-0.4	5.2	3.9	3.5	3.2	3.4	4.0
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	-3.4	3.0	1.7	1.4	1.3	1.8	2.4
उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	3.1	7.5	6.3	5.1	4.7	4.6	5.2
विश्व जिंस व्यापार (परिमाण, % परिवर्तन)	-11.7	14.0	6.6	2.6	2.7	4.3	5.3
विश्व जिंस निर्यात (ट्रिलियन यूएस डॉलर)	12.5	15.2	18.1	18.3	18.6	19.3	20.1
विश्व जिंस निर्यात के मूल्य में वृद्धि (%)	-22.0	21.6	19.5	0.8	1.8	3.7	4.2

टिप्पणी : पी ईएसी, भारत सरकार के पूर्वानुमान, ई अनुमान, एफ पूर्वानुमान, ~परिवर्तन गत वर्ष की अनुरूपी अवधि की तुलना में है, - उपलब्ध नहीं, * - बजट 2014-15 अनुमान, वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2014-15 में 5.4 से 5.9 प्रतिशत के दायरे में, **2009-10 से आंकड़े आईएमएफ भुगतान संतुलन मैनुअल में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर भुगतान संतुलन के आंकड़ों के मानक प्रस्तुतीकरण के नए फॉर्मेट के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए हैं.

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न अंक, केन्द्रीय बजट, भारतीय रिजर्व बैंक की मासिक बुलेटिन, वार्षिक रिपोर्ट एवं साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक, वित्त मंत्रालय, सीएसओ, ईआईयू, नैस्कॉम, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ), डब्ल्यूईओ, आईएमएफ.

चार्ट 1 : 2013-14 में भारत का निर्यात : मासिक एवं प्रतिशत परिवर्तन

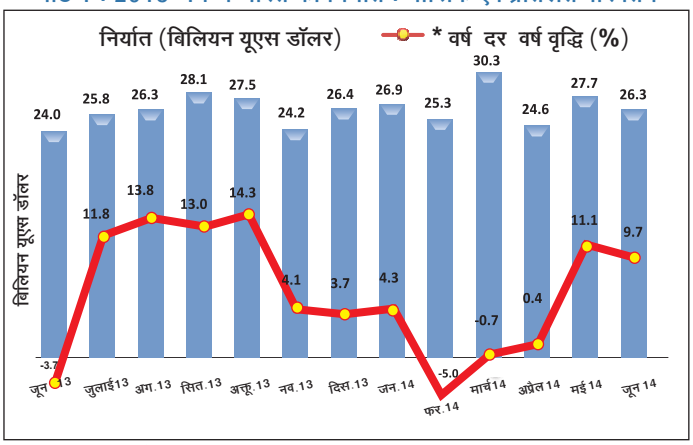

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 2 : 2013-14 में भारतका आयात : मासिक एवं प्रतिशत परिवर्तन

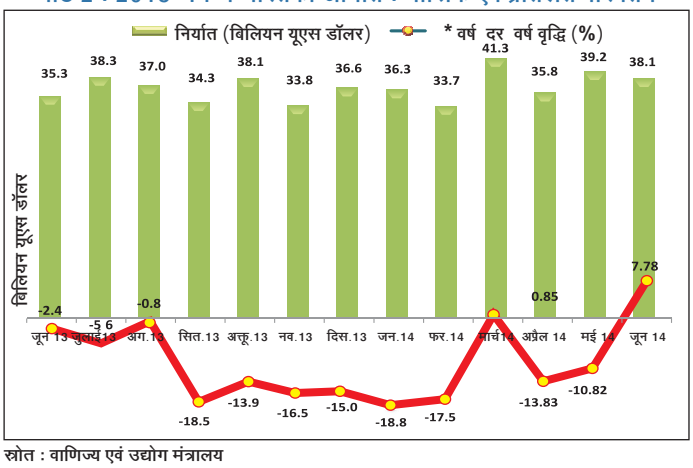

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 3 : 2013-14 में भारत की निर्यात संरचना

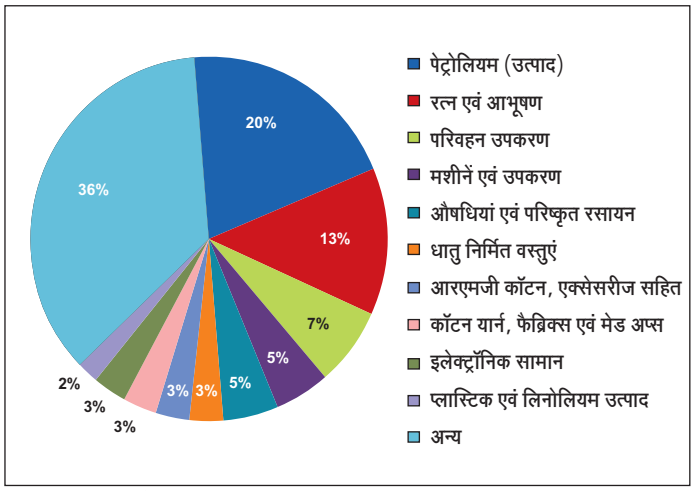

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 4 : 2013-14 में भारत की आयात संरचना

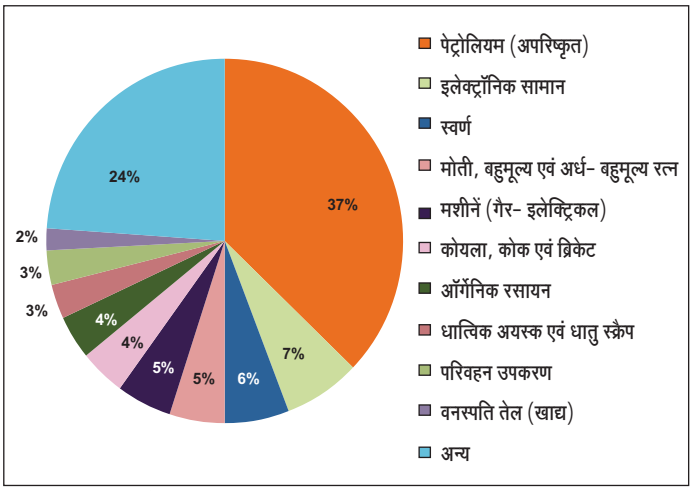

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 5 : विश्व पण्य निर्यात में भारत का हिस्सा

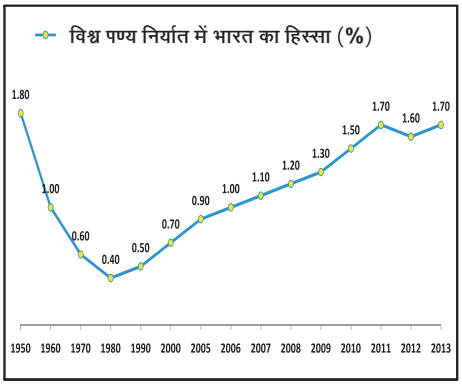

टिप्पणियां : 1) जर्मनी को प्रतिस्थापित करते हुए चीन 2009 में अग्रणी वैश्विक निर्यातक के रूप में उभरा है. 2) भारत 2013 में 19वां सबसे बड़ा वैश्विक निर्यातक बनकर उभरा है जो 2007 के 26वें स्थान और 2000 के 32वें स्थान से ऊपर है.

स्रोत : डब्ल्यू टी ओ (30 जून, 2014 की स्थिति)

चार्ट 6 : विश्व सेवा निर्यात में भारत का हिस्सा

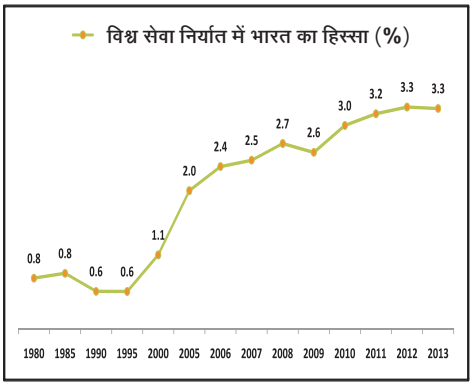

टिप्पणियां : 1) भारत 2013 में छठां सबसे बड़ा वैश्विक सेवा निर्यातक बनकर उभरा है जो 2012 के 7वें स्थान और 2011 के 9वें स्थान, 2009 के 11वें स्थान और 2005 के 15वें स्थान से ऊपर है.

स्रोत : डब्ल्यू टी ओ (30 जून, 2014 की स्थिति)

इसमें प्रकाशित समाचार और जानकारी ऐसे विभिन्न स्रोतों/माध्यमों से एकत्रित की गई है जो अपने आप में प्रमाणिक हैं। प्रकाशित सामग्री की प्रामाणिकता को बनाये रखने में पूरी सावधानी बरती गई है फिर भी इस प्रकार की जानकारी की प्रमाणिकता और यथातथ्यता की कोई जिम्मेदारी एक्ज़िम बैंक की नहीं है।

नोट : भारतीय रुपये का उल्लेख करोड़ और लाख में किया गया है.

1 करोड़ : 10 मिलियन

1 लाख : 100 हजार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक,
केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स,
कफ़ परेड, मुंबई - 400 005
दूरभाष : +91-22-2217 2600
फैक्स : +91-22-2218 2572
ई-मेल : cag@eximbankindia.in
वेबसाइट : www.eximbankindia.in